प्रेरणा स्त्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ..सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

संत और बसंत में एक ही समानता है। जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है और संत आते है तो संस्कृति सुधर जाती है।
पंडित कमल किशोर जी नागर

वर्ष-08, अंक - 35 (साप्ताहिक) खवासा, गुरुवार 18 जून 2026 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

मीनाक्षी मझधार में केवट पहुंचे राज्यसभा में...

माही की गूंज
झाबुआ डेस्क
संजय भटेवरा

राजनीति में जो दिखाई देता है हमेशा वह वास्तविक नहीं होता है और जो नहीं दिखाई देता है वह भी संभव हो जाता है। शायद इसलिए इसे राज-नीति कहा जाता है और इसमें साम-दाम-दंड भेद सभी नीतिया लागू होती है। संविधान निर्माताओ ने राज्यसभा में बुद्धिजीवियों और समाजसेवियों को प्रवेश के लिए बनाया था जो आनुपातिक रूप से राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व देश के उच्च सदन में करें। तथा सभी राज्यों में राज्यसभा सदस्यों का प्रतिनिधित्व निश्चित है। ओर सामान्यतः प्रदेश की विधानसभा चुनाव में दलों को प्राप्त सीटो के आधार पर तय होता है। यानी विधानसभा चुनावो में जिस दल की ज्यादा सिटे उसे राज्यसभा में ज्यादा प्रतिनिधित्व। यानी विधायक के वोटो से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। लेकिन राजनीति का खेल भी बड़ा निराला है पंजाब में भाजपा के विधायकों की संख्या से ज्यादा राज्यसभा के सांसदों की संख्या है। हाल ही में मध्य प्रदेश में 3 सीटों की निर्वाचन प्रक्रिया में गजब का राजनीतिक ड्रामा हुआ और अंततः बाजी भाजपा ने मार ली हैं।

कांग्रेस, मामले को हाई कोर्ट में ले जाना चाहती है और कोर्ट का फैसला जो होना होगा वह होगा लेकिन वर्तमान में तो कांग्रेस खाली हाथ ही है। उसको मिलने वाली एक सीट पर भी भाजपा ने अपना उम्मीदवार उतार कर उसे निर्विरोध निर्वाचित करवा लिया।

कांग्रेस की रणनीतिक चूक

कहते हैं कि, दूध का जला हुआ छाछ भी फुक-फुक कर पीता है लेकिन कांग्रेस ने इस कहावत से भी कोई सबक नहीं लिया। गत लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस इसी प्रकार मात खा चुकी थी जब उसके द्वारा घोषित प्रत्याशी ने अंतिम समय में अपना नाम वापस ले लिया और भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस ने कोई डमी प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था और लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी विहिन हो गई और भाजपा को लगभग वॉक ओवर मिल गया। राज्यसभा चुनावो में भी कांग्रेस में पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को अपना प्रत्याशी घोषित किया और भाजपा ने भी एंडवक्त पर अपना तीसरा प्रत्याशी घोषित कर दिया और जो चुनाव निर्विरोध हो सकते थे उसे रोचक बनाने की कोशिश की।

चुनावो की स्थिति निर्मित होते देख कांग्रेस ने अपने विधायकों की बाड़ावरी शुरू कर दी और विशेष विमान से सभी विधायकों को बेंगलुरु भेजने की तैयारी कर ली थी। यानी घोड़ी और बैंड बाजे सभी तैयार थे बारात पहुंचने वाली थी कि, अचानक खबर आ गई कि दूल्हा गायब है। यानी कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन द्वारा अपने नामांकन में एक आपराधिक मामले की जानकारी नहीं दी गई जिसके चलते उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। विधायको को ले जाने वाला विशेष विमान रनवे से वापस बुलवाना पड़ा। जिसके बाद चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर धरना दिया गया, जगह-जगह विरोध प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में भी प्रदर्शन किया गया, लेकिन कांग्रेस को कोई राहत नहीं मिली। विधायको ने राष्ट्रपति से मिलने की कोशिश भी की लेकिन सफल नहीं हुए। इसी बीच नामवापसी की अंतिम तिथि के दिन भाजपा के तीनों उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित होने का प्रमाण-पत्र भी चुनाव आयोग से मिल गया। अब कांग्रेस इन मुद्दे को कोर्ट में ले जाकर,सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। अब आगे जो भी होता है वह तो भविष्य के गर्त में है लेकिन इस पूरे प्रकरण में प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की आपसी कलह सामने आ गई।

भाजपा नेताओं का कहना है कि, मीनाक्षी नटराजन मामले की जानकारी उन्हें कांग्रेस नेताओं से ही मिली थी। जिसके बाद राज्यसभा के संभावित उम्मीदवारों के बीच आपसी मनमुटाव होना तय है। कांग्रेस के कई नेता राज्यसभा में जाने के लिए तैयार थे कई नेताओं ने इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी थी लेकिन मामला हाथ से जाते देखकर पूरा रायता फैला दिया और मीनाक्षी नटराजन की नया मझधार में अटका दी। वहीं भाजपा के महेश केवट ने अपने नाम अनुरूप अपनी नया पार लगा ली और वह राज्यसभा पहुंच गए।

चढ़ावे में चोरी... आस्था पर आघात...

अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण के लिए देशभर में आन्दोलन हुए थे और मन्दिर को आस्था से जोड़ा गया था। भाजपा जो आज सत्ता शीर्ष पर है उसमें इस मुद्दे का भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। भाजपा ने सत्ता में आने पर कोर्ट के माध्यम से इस विवाद का हल निकाला और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। यही नहीं मंदिर निर्माण के लिए भी देश भर के लोगों ने मुक्त हस्त से दान दिया और रिकॉर्ड समय में भव्य मंदिर के निर्माण का वर्षों पुराना सपना साकार हुआ। भव्य मंदिर पर प्राणप्रतिष्ठा समारोह पूरे देश में उत्साह और उमंग के साथ मनाया और पूरे देश में उत्सव मनाया गया था। हर वर्ग के लोगों के लिए यह क्षण ऐतिहासिक था। यही नहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह की वर्षगांठ भी पूरे देश भर में उत्साह के साथ मनाए जाने लगी। लाखों की संख्या में लोग अयोध्या रामलला के दर्शन हेतु भी पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शनार्थ पहुंच रहे हैं और लाखों रुपए का चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है। लेकिन मंदिर में चढ़ावे में चोरी की खबर ने आम श्रद्धालुओं को विचलित कर दिया है। मंदिर पर चढ़ावा चोरी होना श्रद्धालुओ की श्रद्धा पर गहरा आघात है और इसकी पूरी जांच होना चाहिए तथा दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

क्या है पूरा मामला

दरअसल पुरा मामला सपा सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे के आरोप के बाद सामने आया जिसमें उन्होंने मंदिर के चढ़ावे में से 5 से 7 करोड रुपए चोरी के आरोप लगाए। जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाया और कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया। जिसके बाद भाजपा नेता डॉ. रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर मामले की सीबीआई और ईडी से जांच की मांग की। जिसके पास प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंदिर ट्रस्ट से मामले पर रिपोर्ट मांगी। जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। जिसके बाद इस मुद्दे पर देशभर में चर्चा जारी है। बताया जाता है, श्री राम मंदिर चढ़ावे की चोरी के बाद देशभर में टीनू यादव सुर्खियों में है। टीनू यादव श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के खास सहयोगी हैं और मंदिर ट्रस्ट में पावरफुल बताया जाता है। चाहे सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो या चढ़ावे को बैंक में डिपाजिट करना सब कुछ टीनू ही मैनेज करता आया है।

बताया जाता है कि, रामशंकर यादव उर्फ टीनू यादव के पिता चाय बेचते थे और वह स्वयं ड्राइवर का काम करता था और ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय के संपर्क में आने के बाद वह धीरे-धीरे उनके विश्वास पात्र लोगों में शामिल हो गया। और धीरे-धीरे आलीशान जीवन जीने लगा। टीनू यादव के मोहल्ले के युवको के अनुसार श्री राम मंदिर से जुड़ने के बाद टीनू यादव ने दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की की और चल-अचल संपत्ति जमा कर ली है। टीनू यादव पर आरोप है कि, उसने पिछले 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवाए, 6 से ज्यादा रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप तथा चार-पांच सालों में कई प्लाट खरीदे। ये सब मंदिर में चढ़ावे की चोरी से किया गया है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई हे। लेकिन सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने अयोध्या पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

आम नागरिकों का कहना है कि, पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जा कर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाना चाहिए। क्योंकि अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर केवल अयोध्या या उत्तर प्रदेश का एक मंदिर नहीं है बल्कि देशभर में बसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और मंदिर निर्माण के लिए वर्षों इंतजार किया गया था। यह मंदिर निर्माण किसी सपने के साकार होने जैसा है। ऐसे में करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने वाले को किसी भी कीमत पर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। ताकि फिर किसी मंदिर में इस प्रकार की घटनाओं की पूनरावृतीं ना हो। मंदिर में आम व्यक्ति केवल धन ही नहीं चढ़ता हे बल्कि उस धन के साथ उसकी आस्था भी जुड़ी रहती है और आस्था के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होती है।

जी-7 में मोदी, नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी

एवियन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-7 शिखर सम्मेलन में कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में हाल की घटनाओं से वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है तथा भारतीय नागरिकों की जान भी गई है। उन्होंने कहा कि दुनिया को जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी देशों की जिम्मेदारी है और समुद्री मार्ग सुरक्षित बने रहने चाहिए। नई साझेदारियों का निर्माण और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को पुनर्स्थापित करना विषय पर आयोजित सत्र में मोदी ने कहा कि आज का विश्व पहले से अधिक परस्पर जुड़ा हुआ है और ऊर्जा, खाद्य, स्वास्थ्य तथा साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दे वैश्विक सहयोग से ही सुलझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति कोई खनिज, तकनीक या बाजार नहीं, बल्कि आपसी विश्वास है। विश्व संसाधनों की नहीं, बल्कि विश्वास की कमी से जूझ रहा है। भविष्य की साझेदारियां विश्वास, समानता और सम्मान पर आधारित होनी चाहिए।

साइबर ठगी के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

नई दिल्ली, एजेंसी।

उच्चतम न्यायालय ने साइबर ठगी के एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए साइबर अपराधों के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ऐसे अपराध देशभर के नागरिकों को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं और समाज के व्यापक हित में ऐसे आरोपियों को जेल में ही रहना चाहिए।

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने साइबर अपराधियों की कार्यप्रणाली पर चिंता व्यक्त की। पीठ ने कहा कि इस प्रकार के अपराधी विभिन्न राज्यों में जाकर लोगों को निशाना बनाते हैं और बड़ी संख्या में निवेशकों तथा आम नागरिकों को आर्थिक हानि पहुंचाते हैं। न्यायालय ने टिप्पणी की कि ऐसे मामलों में न्यायपालिका को अत्यंत सतर्क और सख्त दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि साइबर अपराधी एक राज्य में लोगों को ठगने के बाद दूसरे राज्यों में जाकर अपनी गतिविधियां जारी रखते हैं, जिससे उनकी पहचान और गिरफ्तारी की प्रक्रिया जटिल हो जाती है। न्यायालय ने माना कि डिजिटल माध्यमों से होने वाली ठगी अब राष्ट्रीय स्तर की चुनौती बन चुकी है और इससे निपटने के लिए प्रभावी कानूनी कार्रवाई आवश्यक है।

पीठ ने कहा कि ऐसे अपराधों के पीड़ित देश के विभिन्न हिस्सों में फैले होते हैं और कई मामलों में लोगों की जीवनभर की बचत भी दांव पर लग जाती है। इसलिए केवल आरोपी के व्यक्तिगत हित को नहीं, बल्कि समाज और पीड़ितों के हितों को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

व्हाट्सअप पर फर्जी संदेश से इनॉक्स को 10.4 करोड़ की चपत

मुंबई। व्हाट्सअप पर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी बनकर भेजे गए फर्जी संदेश के झांसे में आकर एक कर्मचारी ने 63 बार राशि हस्तांतरित कर दी, जिससे इनॉक्स समूह को 10.40 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। जानकारी के अनुसार, 3 जून को कंपनी के लेखा विभाग के उपमहाप्रबंधक गिरीश अमीन को एक अज्ञात नंबर से संदेश मिला। संदेश भेजने वाले ने स्वयं को कंपनी का कार्यकारी निदेशक सिद्धार्थ जैन बताया और अपने नंबर को निजी नंबर के रूप में सुरक्षित करने को कहा। उसकी प्रोफाइल फोटो भी सिद्धार्थ जैन की थी, जिससे कर्मचारी को विश्वास हो गया। इसके बाद आरोपी ने विभिन्न बैंक खातों में राशि भेजने के निर्देश दिए। 3 से 15 जून के बीच अमीन ने 63 लेन-देन के माध्यम से कुल 10.40 करोड़ रुपये अलग-अलग खातों में भेज दिए। मामले का खुलासा तब हुआ जब अमीन ने आधिकारिक माध्यम से सिद्धार्थ जैन से संपर्क कर भुगतान संबंधी बिल मांगे। जैन ने ऐसे किसी निर्देश से इनकार कर दिया, जिसके बाद धोखाधड़ी का पता चला।

नीट मामले के असली दोषी बच निकले, 15 करोड़ उपयोगकर्ताओं को मिली सजा

नई दिल्ली, एजेंसी।

नीट-यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले परीक्षा संबंधी फर्जी सूचनाओं और कथित नकल गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को लेकर विवाद गहरा गया है। टेलीग्राम के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पावेल ड्यूरोव ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि कुछ लोगों की गलत हरकतों की सजा करोड़ों वैध उपयोगकर्ताओं को भुगतनी पड़ रही है।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 21 जून को होने वाली नीट-यूजी 2026 पुनर्परीक्षा को देखते हुए टेलीग्राम की सेवाएं 22 जून तक अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया है। इसके बाद गूगल ने अपने अनुप्रयोग भंडार से टेलीग्राम अनुप्रयोग हटा दिया है, जबकि एप्पल द्वारा भी इसी प्रकार का कदम उठाए जाने की संभावना जताई जा रही है।

पावेल ड्यूरोव ने सामाजिक माध्यम एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रश्नपत्र लीक या गोपनीय सामग्री साझा करने वाले कुछ लोगों के कारण पूरे मंच को बंद करना उचित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि भारत में टेलीग्राम के 15 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता इस फैसले से प्रभावित हुए हैं, जबकि वास्तविक दोषी वे लोग हैं जिन्होंने परीक्षा से जुड़ी सामग्री का दुरुपयोग किया।

ड्यूरोव के अनुसार, टेलीग्राम पर रोक लगाने से कथित प्रश्नपत्र लीक या गलत सूचना फैलाने वाली गतिविधियां समाप्त नहीं हुई हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग दूसरे डिजिटल मंचों पर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि टेलीग्राम ने परीक्षा सामग्री लीक और फर्जीवाड़े से जुड़े सैकड़ों माध्यमों को हटाया है तथा संदेशों में संशोधन की पहचान को और स्पष्ट बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

एनटीए का कहना है कि टेलीग्राम की संदेश संशोधन सुविधा का कुछ मामलों में दुरुपयोग किया गया। आरोप है कि परीक्षा समाप्त होने के बाद कुछ संदेशों में बदलाव कर उन्हें पूर्व में हुए प्रश्नपत्र लीक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। इसी कारण सरकार ने टेलीग्राम को भारत में अपनी संदेश संशोधन सुविधा पर भी 30 जून तक अस्थायी रोक लगाने का निर्देश दिया है।

एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि यह कार्रवाई किसी नए प्रश्नपत्र लीक की घटना के कारण नहीं, बल्कि परीक्षा से जुड़े फर्जी संदेशों और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए की गई है।

नीट अभ्यर्थियों की मौतें भ्रष्ट व्यवस्था का परिणाम - राहुल गांधी

कोटा।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार को छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कोटा पहुंचे। चार्टर विमान से कोटा हवाई अड्डे पहुंचने पर उनका स्वागत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट सहित कई नेता मौजूद रहे।

राहुल गांधी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। भारी भीड़ के कारण पुलिस को व्यवस्था संभालनी पड़ी तथा काफिले को बाहर निकालने में भी मशक्कत करनी पड़ी।

इसके बाद राहुल गांधी स्टेशन रोड स्थित एक निजी होटल पहुंचे, जहां उन्होंने चुनिंदा छात्रों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। बाद में उन्होंने दशहरा मैदान में आयोजित 'छात्रों की गूंज' संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम में केवल छात्रों को प्रवेश दिया गया था। कोटा आगमन से पूर्व राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर संदेश जारी कर हाल ही में नीट पुनर्परीक्षा के दबाव में जान गंवाने वाले छात्रों उमेश और रिया का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियों और भ्रष्ट तंत्र का परिणाम है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रश्नपत्र लीक, कुप्रबंधन और अनियमितताओं के मामलों के बावजूद छात्रों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि युवाओं के सपनों की रक्षा और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए व्यापक संघर्ष की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि कोटा से शुरू किया गया यह अभियान छात्रों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास है। ताकि भविष्य में किसी छात्र और उसके परिवार को ऐसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े।

पुलिस का सराहनीय कार्य, आरोपी गिरफ्तार

सस्ते मोबाइल की लालच में व्यापारी हुआ था ठगी का शिकार

माही की गूंज, झाबुआ/थांदला।

हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि, लालच बुरी बला है, लेकिन हम जब इस बात का अनादर करते हैं तो हम ठगी के शिकार बनते ही हैं।

उक्त वाक्य को चरितार्थ थांदला के एक व्यापारी ने किया और लालच में आकर बड़ी ठगी का शिकार भी हुआ। मामला यह कि, थांदला के जवाहर मार्ग निवासी रवि गादिया, जो कि मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के व्यापारी हैं। व्यापारी रवि गादिया के पास एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आता है और वह अपने आपको मोबाइल का बड़ा व्यापारी बताते हुए वीवो कंपनी के बीस मोबाइल फोन बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर उपलब्ध कराने का लालच दिया था। वही थांदला व्यापारी अपने बुजुर्गों की बात भूलकर लालच में आ गया और ठगी का शिकार हुआ। सस्ते मोबाइल मिलने की लालच में महंगे बीस मोबाइल का सौदा कम भाव में 2 लाख 52 हजार 680 रुपए में अज्ञात ठगोंरे से व्यापारी ने फोन पर तय किया था। तय सौदे अनुसार 1 लाख 92 हजार रुपए एनईएफटी तथा 60 हजार 680 रुपए फोन पे के जरिए ट्रांसफर कर दिए।

उक्त घटना 6 जून 2026 की बताई जा रही है। राशि ट्रांसफर करने के बाद जब थांदला के व्यापारी ने पुनः उस मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की जिससे फोन आया था। लेकिन उक्त ठगोरे का मोबाइल सतत बंद ही पाए जाने पर थांदला व्यापारी को ठगी का एहसास हुआ। जिसके बाद व्यापारी रवि गादिया ने थांदला थाने में मामला दर्ज करवाया।

उक्त मामले को एसपी देवेंद्र पाटीदार ने अपने संज्ञान में लेकर त्वरित मामले को ट्रेस करने के निर्देश दिए। एसपी के निर्देश के साथ साइबर एवं थांदला थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने तकनीकी सहायता के साथ आरोपी की लोकेशन महाराष्ट्र के पालघर जिले में ट्रेस की। तत्पश्चात थांदला थाने व साइबर पुलिस टीम ने महाराष्ट्र के पालघर जिले की पुलिस की सहायता से आरोपी की घेराबंदी की और आरोपी रोशन शर्मा को गिरफ्तार करने में सफलता मिली।

वहीं आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि, ठगी की राशि अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर की जानी थी। स्थानीय बैंक से संपर्क कर पुलिस ने ठगोरे के बैंक खाते में 2 लाख 6 हजार 493 रुपए की राशि को होल्ड करवा दिया। पुलिस की उक्त त्वरित कार्यवाही एवं सफलता की माही की गूंज परिवार सराहना करता है।

महाराष्ट्र से आरोपी रोशन शर्मा गिरफ्तार।

चालाक लोमड़ी ठगी का शिकार कैसे...? बना चर्चा का विषय

कहते हैं लालच व्यक्ति की आंखों पर पट्टी बांध देता है और फिर उसे दूसरा सही क्या है, यह पहलू दिखाई ही नहीं देता है। लेकिन कोई चालाक लोमड़ी या सट्टा-जुआ खेलने व संचालित करने वाला व्यक्ति इस तरह के लालच में आकर ठगी का शिकार हो जाए तो नगर में चर्चा का विषय तो बनता ही है। उक्त मोबाइल व्यापारी लालच में आकर सस्ते मोबाइल खरीदने के चलते ठगी का शिकार होने पर नगर में चर्चा का विषय है कि उक्त व्यापारी आईपीएल जुए का आरोपित है और गांव में बड़े व्यापारी व चालाक लोमडी के रूप में पहचान भी है। ऐसे में सस्ते व चार सौ बीसी तथा चोरी जैसे मोबाइल की खरीदी के नाम पर ठगी का शिकार कैसे हो गया...? इसकी चर्चा नगर में चल रही है।

मोबाइल व्यवसायियों की मानें तो हर मोबाइल कंपनी का होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर होता है और उसी से मोबाइल विक्रेताओं को मोबाइल खरीदना होता है, जिसमें प्रत्येक मोबाइल व्यापारी को 4 से 15 दिन तक की पेमेंट देने की सुविधा भी मिलती है। कई बार कंपनियों की स्कीम के साथ टारगेट होते हैं, जिनमें अतिरिक्त कमीशन मिलता है। जैसे कि, किसी व्यापारी ने महीने में टारगेट अनुसार 50 मोबाइल बेचने का लक्ष्य लिया है और स्कीम के तहत पचास मोबाइलं बिक्री नहीं हो कर 35 या 40 मोबाइल ही बिके हों। ऐसे में यह व्यापारी छोटे एवं परिचित मोबाइल विक्रेताओं से संपर्क कर 500 से लेकर 1500 या अधिक कम रूपयों में मोबाइल दे कर बिल के साथ सौदा तय होता है। इसमें होता यह है कि मोबाइल का इंस्टॉलेशन सिम डालकर करना होता है, जिसमें इंस्टॉलेशन दिनांक से उसकी वारंटी शुरू हो जाती है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़ अन्य जगह कहीं पर यह छूट नहीं मिलती है। ऐसे में अगर अपरिचित व्यक्ति से इस तरह सस्ते मोबाइल खरीदे जाएं तो व्यापारी चोरी के मोबाइल भी खरीदने में आ सकता है।

थांदला नगर की चर्चा में यही आ रहा है कि, थांदला का यह व्यापारी सस्ते मोबाइल खरीदने के चक्कर में चोरी के मोबाइल भी खरीद लेता क्या..? अगर ऐसा होता तो उक्त व्यापारी के साथ वह खरीदार भी आरोपित बनता, जो उक्त दुकान से मोबाइल खरीदता। मोबाइल के आईएमईआई नंबर से अगर चोरी के मोबाइल होते तो ट्रेस होने पर व्यापारी की लालच के चलते खरीदार भी आरोपित बन सकता था।

ऐसे में माही की गूंज अपील करता है कि, लालच में आकर ठगी का शिकार न हों और ऐसे लालची व्यापारियों से भी बचें, जो सस्ते मोबाइल खरीदकर बेचें। समझदार बनें, सतर्क रहें।

फर्जी रजिस्ट्री का मास्टर मांइड डाक्टर डाबी लापता

सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज, पुलिस ने इनाम किया घोषित

माही की गूंज, पेटलावद।

डा. डाबी।

पेटलावद थाना क्षेत्र में जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कर धोखाधड़ी करने वाले तीन फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक झाबुआ ने 5 हजार रुपए के नगद इनाम की घोषणा की है। पुलिस ने आरोपियों की सूचना देने अथवा गिरफ्तारी में सहयोग करने वाले व्यक्ति का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। पुलिस के अनुसार अपराध क्रमांक 68/2026 में फरियादी मकना पिता मांडया गणावा निवासी पीपलीपाडा की शिकायत पर जांच की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि, उसकी जमीन को फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी पूर्वक बेच दिया गया। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि, आरोपी डॉ. नरसिंह डाबी, माला पिता देवा गणावा तथा प्रॉपर्टी ब्रोकर प्रताप गामड़ ने आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए फरियादी के वोटर कार्ड में कूटरचना की।

आरोपियों ने फरियादी मकना के वोटर कार्ड पर उसकी फोटो हटाकर माला की फोटो लगाई और फर्जी पहचान के आधार पर ग्राम माण्डन स्थित सर्वे क्रमांक 1565 की 0.35 हेक्टेयर भूमि की रजिस्ट्री करा दी। इस प्रकार आरोपियों ने छल-कपट एवं जालसाजी कर जमीन का फर्जी विक्रय पत्र तैयार कराया। पुलिस जांच में मामला सही पाए जाने के बाद आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया, लेकिन घटना के बाद से तीनों आरोपी फरार चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु अब तक सफलता नहीं मिल सकी है।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक झाबुआ देवेन्द्र पाटीदार ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी या उनके संबंध में पुख्ता सूचना देने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की है।

कहा है डाक्टर डाबी

पुलिस को इस मामले में जिन आरोपियों की तलाश है उसमें डॉ. नरसिंह डाबी पिता हीरालाल डाबी, निवासी देवरापाड़ा (मोहनपुरा) क्रेता, माला पिता देवा गणावा, निवासी ग्राम बनी, थाना रायपुरिया - फर्जी विक्रेता, प्रताप पिता भेरूलाल गामड़, निवासी ग्राम बनी -प्रॉपर्टी ब्रोकर है। इसमें से डाक्टर डाबी सिविल हॉस्पिटल पेटलावद में पदस्थ हैं और उक्त मामले के बाद से लगातार फरार है। बताया जा रहा है इस मामले में डाक्टर डाबी ने निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अग्रिम जमानत का प्रयास भी किया लेकिन वहां भी जमानत नहीं मिली। अब पुलिस लगातार डाक्टर की खोजबीन कर रही है ओर अब इनाम तक घोषित हो चुका है।

तनाव का माहौल बनाने वाले पर कार्यवाही

माही की गूंज, थांदला।

कई बार देखने में आता है कि, किसी छोटी सी बात पर भी बहस दो पक्षों में इतनी बढ़ जाती है कि वह बड़े विवाद का रूप ले लेती है। इस तरह के विवाद से गाँव व नगर में तनाव व डर का माहौल भी बन जाता है, लेकिन पुलिस इस तरह के मामले को नजरअंदाज कर देती है और माहौल और ज्यादा बिगड़ने की संभावना बनी रहती है।

लेकिन थांदला में मठ वाले कुएं के समीप शनिवार को किसी बात पर दो गुटों में विवाद हुआ और आमने-सामने एक-दूसरे को जान से मारने तक उतारू हो गए। तथा उक्त घटना से नगर में अशांति फैलकर तनाव का माहौल बन गया। उक्त विवाद का वीडियो जब वायरल हुआ तो थांदला पुलिस ने अपनी सजगता दिखाई और पुलिस जांच में सामने आया कि, किसी पुरानी दुर्घटना को लेकर पास के गाँव बड़ा गुड़ा के दो पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। शनिवार को दोनों पक्षों का आमना-सामना थांदला में हुआ और गाली-गलौज के साथ विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया तथा नगर में तनाव का माहौल बन गया।

सार्वजनिक स्थल पर हुए उक्त विवाद को पुलिस ने कानून व्यवस्था व सामाजिक शांति के लिए गंभीर माना तथा पुलिस ने मौके पर पहुँचकर सार्वजनिक जगह पर तनाव फैलाने वालों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जिसके बाद न्यायालय ने आरोपियों को जेल भेजा।

गौवंश के अवशेष मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

हिंदू संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, देर रात तक चला धरना

माही की गूंज, रतलाम।

जिले के सैलाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात गौवंश के अवशेष मिलने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया।घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। पुलिस को सूचना देकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई।

रतलाम-बांसवाड़ा मार्ग स्थित चरण पेट्रोल पंप के पास, नर्सिंग कॉलेज से आगे सड़क किनारे पथरीले क्षेत्र में देर रात करीब 12 बजे गौवंश का सिर समेत शरीर के अलग-अलग कटे हुए अवशेष आसपास मिले। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जांच शुरू की। घटना की सूचना पर एसडीएम तरुण जैन, तहसीलदार कुलभूषण शर्मा, एसडीओपी नीलम बघेल, थाना प्रभारी पिंकी आकाश सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों और संगठन पदाधिकारियों से चर्चा कर शांति बनाए रखने की अपील की।

पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है। मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। आसपास के क्षेत्र की जानकारी जुटाने के साथ संभावित संदिग्धों की तलाश भी की जा रही है।

गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे कार्यकर्ता

घटना के विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता देर रात सड़क पर धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। धरना बुधवार तड़के सुबह करीब 5 बजे तक जारी रहा। प्रशासन की ओर से मामले की गंभीरता से जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद धरना समाप्त किया गया। संगठन पदाधिकारियों ने दो दिनों के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी है।

पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और तथ्य सामने आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने तथा सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति सामान्य है और पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है।

क्षीर धारा ग्राम योजना से जुड़ा ग्राम बरवेट

माही की गूंज, बरवेट।

मध्य प्रदेश सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से जिले के बरवेट ग्राम को 'क्षीर धारा ग्राम योजना' से जोड़ा गया है। इस योजना के तहत पशुओं के स्वास्थ्य, टीकाकरण और नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी के अंतर्गत जिला पंचायत सीईओ जितेंद्र चौहान, पशुपालन विभाग झाबुआ के उपसंचालक डॉ. दिवाकर बरवेट पहुंचे तथा पशुपालकों से सीधे संपर्क किया। उन्होंने ग्राम बरवेट की लखपति दीदी एवं नारीशक्ति की पहचान बन चुकी सरस्वती पाटीदार के डेयरी फार्म पर जाकर निरीक्षण किया।

उन्होंने बताया कि उक्त डेयरी फार्म पूर्ण रूप से उन्नत तरीके से संचालित किया जा रहा है, जिसमें पशुओं का शत-प्रतिशत कृत्रिम गर्भाधान सेक्स-सॉर्टेड सीमेन से करवाया जा रहा है। जिससे मादा बछिया पैदा होती है। वह बड़ी होकर गाय बनती है और आगे बछिया को जन्म देकर एक दिन में 40 लीटर दूध का उत्पादन लिया जा सकता है।

योजना के तहत चयनित ग्रामों में पशुपालकों को उन्नत नस्ल के पशुओं के पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही बेहतर पशु चिकित्सा सेवाएं, नियमित टीकाकरण, उच्च गुणवत्ता युक्त पशु आहार उपलब्ध कराना तथा गुणवत्तापूर्ण चारे के उत्पादन हेतु प्रेरित किया जाएगा, ताकि दुग्ध उत्पादकता में स्थायी बढ़ोतरी हो सके।

बीएमओ डॉ. एमएल चोपड़ा को जिला स्वास्थ्य अधिकारी का प्रभार

माही की गूंज, पेटलावद।

मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक आधार पर अधिकारियों के तबादलों के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार डॉ. एम.एल. चोपड़ा, जो कि वर्तमान में पेटलावद, जिला झाबुआ में मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी (सीबीएमओ) के पद पर पदस्थ थे, उन्हें प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ), जिला झाबुआ के पद पर पदस्थ किया गया है। शासन के आदेश के अनुसार यह पदस्थापना तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। डॉ. चोपड़ा के सीएमएचओ बनने से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत प्रदेश के कई वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के भी स्थानांतरण किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश में संबंधित अधिकारियों को शीघ्र नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

रेलवे ट्रैक के समीप मिला था शव, शिनाख्त होने के आरोपियों की तलाश में पुलिस

माही की गूंज ,बामनिया।

पेटलावद थाना अंतर्गत बामनिया चौकी क्षेत्र में बिजनीपाडा के पास रेलवे पटरी के समीप 11जून को अज्ञात शव कि शिनाख्त बहादुर पिता देवला भूरिया निवासी ग्राम सेमलिया चौकी खवासा तहसिल थांदला के रूप में हुई थी। परिजनों के अनुसार मृतक तीन दिन से लापता था। जिस स्थिति में शव बरामद हुआ था जिससे युवक की हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। मामले में फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस जल्द ही इस मामले का खुलासा कर सकती हैं। जानकारी के अनुसार बुधवार को पुलिस अधीक्षक ओर पेटलावद थाने के बड़े अधिकार बामनिया चौकी भी पहुंचे। जिससे कयास लगाए जा रहे है कि मामले में पुलिस जल्द ही खुलासा कर सकती है।

चौकी प्रभारी मालिवाड से इस संबंध में चर्चा की तो उन्होंने मामले में कोई जानकारी नहीं देते हुई जांच की बात कही। यहां तक कि युवक की पीएम रिपोर्ट में मौत के कारण क्या बताए गए उसके लिए भी पीएम रिपोर्ट नहीं आने की बात कही गई।

जन कल्याण शिविर में पहुंचे जिला कलेक्टर, लोगों की समस्याओं का हुआ समाधान

माही की गूंज, बरवेट।

ग्राम बरवेट की आठ ग्राम पंचायत बावड़ी डाबरी, हमीरगढ़, देवली, बाछीखेड़ा, मोहुडीपाड़ा, तेमरिया, अनंतखेड़ी पंचायत के ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर शिविर में उपस्थित हुए। तीन दिवसीय जनकल्याण शिविर के तीसरे दिन बुधवार को जिला कलेक्टर योगेश तुकाराम भरसट के साथ पेटलावद एसडीएम बरवेट पहुंचे और लोगो की समस्याओं को सुना। वही पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। कलेक्टर ने जनकल्याण शिविर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि, इस शिविर का मुख्य उद्देश्य राज्य और केंद्र शासन की जनहितकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना और आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। शिविर में पेंशन, राशन, आयुष्मान कार्ड, और आवास जैसी योजनाओं से जुड़े आवेदन लिए गए तथा कई मामलों का मौके पर ही निराकरण कर योजनाओं का लाभ दिया।

ग्रामीण ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप दिया आवेदन

कलेक्टर भरसट के शिविर में पहुचने के बाद ग्रामीण पारस पाटीदार ने ग्राम पंचायत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया। सामुदायिक भवन निर्माण में भ्रष्टाचार चरम पर हुआ है, एस्टीमेट के हिसाब से निर्माण नही किया गया है। वही मुक्तिधाम निर्माण, बरवेट हमीरगढ़ मार्ग से मुक्तिधाम तक सड़क निर्माण में अनियमितता बरती गई है। मुक्तिधाम निर्माण, नल जल योजना के अंतर्गत कूप निर्माण के भी भारी अनियमिता बरती गई है। जिसका आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है।

अजब गजब पंचायत बरवेट

ग्राम पंचायत बरवेट भी अजब गजब है। यहां पर चार साल के कार्यकाल में पांच पंचायत सचिव बदले गए है। सबसे पहले सचिव कैलाश भाभर इसके बाद रामकिशन वर्मा, उसके बाद लक्ष्मण मुनिया इसके बाद दिनेश लिमडिया इसके बाद हुरजी मेड़ा प्रशासनिक तबादले की नीति लागू होने के बाद ग्राम पंचायत बरवेट को सचिव मिला है। चार साल के कार्यकाल में पांच सचिव का बदलना हर किसी के लिए हास्य का विषय बन चुका है।

बदनावर-टिमरवानी फोरलेन रोड के मुआवजे को लेकर भड़के किसान

एक बार फिर दिखेगा क्षेत्र में बड़ा किसान आंदोलन, कार्यालय का हुआ शुभारंभ

किसान कार्यालय का हुआ उद्घाटन।

जमीन नहीं देने और उचित मुआवजा राशि को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे प्रभावित किसान परिवार।

माही की गूंज, पेटलावद।

बदनावर से टिमरवानी तक बनने वाले फोरलेन रोड को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। यहां किसान रोड में जा रही अपनी जमीन के लिए मुआवजे की राशि को लेकर बहुत नाराज हैं। किसानों ने अब अपनी जमीन के सही मुआवजे के लिए सड़क पर उतरने का मन बना लिया है। पिछले कुछ दिनों से किसानों ने जनसुनवाई से लेकर अनुविभागीय अधिकारी तक अपना विरोध दर्ज करवाया है। कम मुआवजा राशि को लेकर किसान भड़के हुए हैं उनका यह कहना है कि, निराकरण होने तक एक इंच जमीन रोड निर्माण एजेंसी को नहीं देंगे।

जिन किसानों की जमीन रोड में जा रही है, उनकी बैठकों का दौर शुरू हो गया और बड़ी संख्या में किसान रात में हो रही बैठकों में भाग ले रहे हैं और मुआवजा राशि को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। किसानों ने इस मामले को लेकर एक संगठन बनाने की तैयारी कर ली है, जो पूरे मामले को लेकर सड़क से लेकर न्यायालय तक कानूनी लड़ाई लड़कर अपना अधिकार मांगेगा। सोमवार को पेटलावद में किसान कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जहां से उचित मुआवजा राशि के लिए लड़ाई की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

किसान महेंद्र हामड़ ने बताया कि, मेरी जमीन करड़ावद में है, जो रोड निर्माण में जा रही है, लेकिन सरकार की घोषणा के विपरीत बहुत कम मुआवजा राशि दी जा रही है और किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव ली जा रही है।

उधर, बाप पार्टी के विधानसभा प्रभारी धर्मेंद्र डामोर के नेतृत्व में भी सोमवार को एक ज्ञापन इस मुद्दे को लेकर दिया गया। धर्मेंद्र डामोर ने बताया कि, जिले में पांचवीं अनुसूची लागू है, इसके बाद भी उसका पालन नहीं किया जा रहा है। गरीब आदिवासी से उसकी रोजी-रोटी छीनी जा रही है और बदले में उसे मुआवजे के नाम पर मामूली झुनझुना पकड़ा दिया जा रहा है, जिसमें जमीन के बदले जमीन तो ठीक, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं खरीदा जा सकता।

जयस जिला प्रभारी प्रकाश डामोर ने बताया कि, हम किसानों के साथ हैं। जिनकी जमीन जा रही है, उन्हें पर्याप्त मुआवजे के साथ-साथ जमीन के बदले जमीन मिलनी चाहिए। सरकार उद्योग और सड़क निर्माण के नाम पर उनकी जमीन और रोजगार छीनकर उनका शोषण कर रही है।

देखा जाए तो इस मामले में प्रशासन के सामने कड़ी चुनौती आने वाली है और किसान कम और न के बराबर मिल रही मुआवजा राशि को लेकर खासे नाराज लग रहे हैं। उधर प्रशासन, किसानों को सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही मुआवजा राशि देने की बात कर रहा है।

नए सीएमएचओ डॉ. एमएल चौपड़ा ने संभाला पदभार, स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी नई गति

माही की गूंज, झाबुआ।

झाबुआ जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए डॉ. एमएल चौपड़ा ने मंगलवार को प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) के पद का विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया। उनके पदभार संभालने के साथ ही जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा और गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश के तहत डॉ. एमएल चौपड़ा को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले वे पेटलावद में मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी (सीबीएमओ) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे और अपने कार्यकाल के दौरान बेहतर प्रबंधन एवं जनहितकारी कार्यों के लिए पहचाने जाते रहे हैं।

पदभार ग्रहण करने के बाद डॉ. एमएल चौपड़ा ने कहा कि, जिले के प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। शासकीय अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं को और बेहतर बनाने, ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के सफल क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि, स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम के साथ समन्वय स्थापित कर पारदर्शी एवं जवाबदेह कार्यप्रणाली विकसित की जाएगी, जिससे मरीजों को समय पर उपचार और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी नए सीएमएचओ का स्वागत करते हुए बेहतर नेतृत्व में जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद व्यक्त की है। विशेष रूप से दूरस्थ आदिवासी अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में नए प्रयास किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

प्रभारी तहसीलदार अनिल बघेल का हुआ स्थानांतरण, अच्छा रहा कार्यकाल

माही की गूंज, पेटलावद।

कुछ माह पूर्व ही पेटलावद प्रभारी तहसीलदार के रूप में पदस्थ हुए नायब तहसीलदार अनिल बघेल का स्थानांतरण धार जिले के लिए हो गया। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा थोकबंद तबादलों की सूची हर विभाग से आ रही है। राजस्व विभाग में पदस्थ तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के ट्रांसफर किए गए हैं। सूची में जिले के भी पांच नाम शामिल हैं। पेटलावद में पदस्थ तहसीलदार अनिल बघेल का भी स्थानांतरण किया गया।

वैसे तो अनिल बघेल का कार्यकाल थोड़ा छोटा रहा, लेकिन अच्छे कार्यकाल के साथ उनकी विदाई हो रही है। उनके कार्यकाल के दौरान कई बार किसान आंदोलन के लिए सड़क पर उतरे, जिनको सूझबूझ से उन्होंने निपटाया। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के मामलों में भी तहसीलदार बघेल ने कई मामलों के निराकरण करने में सफलता प्राप्त की। जमीन विवाद में निर्णयों के बाद भूमि मालिकों को कब्जा दिलवाने का रिकॉर्ड भी अच्छा रहा। एसआईआर का कार्य भी बघेल के नेतृत्व में पेटलावद विकासखंड में सबसे पहले पूर्ण किया गया।

कुल मिलाकर छोटा कार्यकाल कई उपलब्धियों से भरा रहा है। एक ओर जहां एसडीएम तनुश्री मीणा आम जनता, कर्मचारियों और किसानों से सामंजस्य नहीं बना पाईं, वहीं बघेल अपनी समझदारी से सभी मामलों में उनकी ओर से बिगड़ती व्यवस्था को संभालने में सफल रहे। पेटलावद विकासखंड और झाबुआ जिले से अच्छी यादें लेकर अब वे धार जिले में अपनी सेवाएं देंगे। हालांकि, नए तहसीलदार के आने तक पेटलावद की जिम्मेदारी उन्हीं के पास रहेगी।

लायंस क्लबः नवीन कार्यकारिणी का गठन

माही की गूंज, थांदला।

स्थानीय गणेश मंदिर परिसर में लायंस क्लब थांदला की बैठक वर्तमान अध्यक्ष लायन चिराग घोड़ावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जुलाई 2026 से जून 2027 तक के नवीन सत्र के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया।

बैठक में लायन प्रकाश घोड़ावत ने आगामी अध्यक्ष पद के लिए लायन डॉ. ओमप्रकाश बजाज के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। वहीं, लायन उमेश पिचा ने सचिव पद के लिए लायन दिनकर बाजपेई तथा लायन प्रशांत उपाध्याय ने कोषाध्यक्ष पद के लिए लायन सावन गर्ग के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की।

डॉ. ओमप्रकाश बजाज।

इसके अलावा प्रथम उपाध्यक्ष पद पर लायन प्रकाश घोड़ावत का मनोनयन किया गया।

लायंस क्लब थांदला विगत 46 वर्षों से थांदला एवं आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न सेवा गतिविधियों के माध्यम से समाजसेवा का कार्य करता आ रहा है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश बजाज ने कहा कि, नवीन कार्यकारिणी सेवा गतिविधियों को और अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित रूप से संचालित करेगी। क्लब द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात जागरूकता अभियान, योग, देशप्रेम एवं ग्रामीण अंचलों में जनहित के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नई कार्यकारिणी अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करेगी।

मुफ्त सुविधाओं से गरीबी मिटाने के प्रयास सार्थक सिद्ध हो सकते हैं या सरकार दे रही परजीवियों को जन्म

माही की गूंज, झाबुआ।

राजनीति दलों में दावों के मुफ्त वादें नागरिको को आलसी, कमजोर, निर्लज, नाकारा, बनाती जा रही है। देश के उच्चतम न्यायालय ने भी लोकलुभावन घोषणाओं में लोगों को प्रलोभन के जाल में फंसते देखा है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने राजनीतिक दलों को आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि, राष्ट्रीय विकास के लिए लोगों को मुख्य धारा में लाने के बजाए रेवड़ी की राजनीति से देश में हम परजीवियों का एक वर्ग तैयार कर रहे हैं। यह भारत देश का दुर्भाग्य है कि, चुनाव से ठीक पहले घोषित रेवड़ियों से लोग काम करने के लिए तैयार नहीं होते। उन्होंने मुफ्त में मिलने वाली सामग्री, राशन और पैसो पर अपने जीवन को आधारित कर लिया है, जिसके लिए नागरिको में जागरुकता लाने की आवश्यकता अधिक है।

वर्तमान में देशभर में अनेक मुफ्त योजनाओं में करोड़ो नागरिक लालच में स्वयं के स्वाभीमान को खोते जा रहे हैं। भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी राजनीति के सारे समीकरण बदल दिए। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त परिवहन से मुफ्तखोरी की राजनीति को अलग स्तर पर ले गए, जो की जनकल्याण और देश के विकास पर बोझ है। कांग्रेस भले ही चुनावों में विजय प्राप्त नहीं कर पाई हो लेकिन उसने भी चुनाव जीतने के लिए बड़े-बड़े वादों के दावे किए। भाजपा भी रेवड़ी संस्कृति के सम्पर्क से दिल्ली में 27 वर्ष बाद अपने ध्वज को फहराने मे सफल हुई थी वहीं बंगाल, असम जैसे राज्यों में भी सफलता का ढ़ोल बजाया।

संविधान में निर्दिष्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में केंद्र और राज्य सरकारों को नागरिकों का जीवन स्तर सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश है। परंतु सरकारों ने तो निःशुल्क सुविधाएं चलाकर आर्थिक स्थिती को दरकिनार कर दिया।

कुछ लोगों का मत है कि, जो अत्यंत निर्धन वर्ग के लोग है उन्हें सुविधाएं मिलती है तो ठीक भी है। लेकिन प्रश्न यही है कि, उनको भी कब तक निशुल्क सुविधाएं मिले? क्योंकि हमेशा देखा गया है सुविधाओं को पाने के लिए कामचोर, लालची वर्ग अपने आप को गरीबी रेखा से नीचे दर्शाने के लिए अति निर्धन भी बन जाते हैं। फिर राजनैतिक दल अपनी रोटियां सेकने के लिए रेवड़ियों का साधन चुनते हैं और उन निर्धनों के साथ करोड़ो जनता को मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी देकर निठल्ला बनाते हैं। देश में जानबूझ कर सोते रहने वालो की संख्या में बड़ोत्तरी होती जाती हैं और कामकाजी लोग कम होते जा रहे हैं, इसीलिए भी जागरुकता की रैली में मुट्ठीभर लोग ही शामिल हो पाते हैं।

वंचितों को वितरणात्मक प्रणाली से जोड़ कर मुख्यधारा में लाने का प्रयास स्वाभाविक है किंतु अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सरकारी खजाने को कितनी बड़ी कीमत चुकानी होती है इसका अंदाजा लगना आम जनता के लिए मुश्किल है ही। क्योंकि भ्रष्टाचार का जन्म इसी प्रकार से ऐसे ही स्थानों से होता है। साथ ही साथ मुफ्त सुविधा की योजनाओं से सरकार, जनता को निठल्ला और नाकारा बना रही है जो कि आने वाली युवा पीढ़ी के लिए घातक है। मनोवैज्ञानिक दृष्टीकोण से देखा जाए तो लोगों को बहुत कुछ वस्तुएं सहजता से प्राप्त हो जाने की स्थिति में उनका पुरुषार्थ का भाव धीरे-धीरे घटने लगता है।

सुविधा तो ऐसी दी जानी चाहिए कि, व्यक्ति उस सुविधा को पा कर अपने विकास की ओर अग्रसर होने की शुरुआत करे जिससे धीरे-धीरे वह सुधार की स्थिती में तो आएगा ही और बेकार लालची भी नहीं बनेगा। सुविधाएं लेने वालों को समझदार होने की तरफ जागरुक करना होगा अन्यथा इसका मुल्य किस तरह घातक हो सकता है आप और हम उस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। रेवड़ी राजनीति या मुफ्त सुविधाओं के परिणाम से होने वाली हानियों का फल राजनीतिक दल नहीं लेगें। इसका घातक मुल्य तो जनता को ही चुकाना होगा, और ऐसा मुल्य चुकाना होगा कि आने वाली पीढ़ी को उचित स्तर के जीवन के लिए आवश्यक सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य का स्थान प्रमुख होगा। यहां इस बात की प्राथमिकता में श्रेष्ठता है कि, भूखे को भोजन करवाने से कई गुना अधिक यह श्रेयस्कर है कि उस भूखे को वह कौशल या तौर तरिके सीखाए जाए जिससे भूखमरी कभी भी उसे या उसके परिवार के पास न आए। साथ ही इसके सरकार द्वारा लोगों को कार्य करने और विकासशील होने के लिए प्रेरित करना होगा।

मुफ्त की इन सुविधाओं से चुनाव तो जीते जा सकते हैं, मगर भविष्य में इसकी बहुत बड़ी किमत उन्हीं को चुकानी होगी जिन्होंने लोभ-लालच में मुफ्त सुविधाओं के लिए मतदान किया होता है। जनता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि, राजनीतिक दलों की ये आकर्षक स्कीमें महज अस्थायी राहत देती है। जब दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं पर अध्ययन किया गया जिसमें सुविधाओं का आर्थिक, सामाजिक, नैतिक प्रभाव की जांच की गई। तब इस विश्लेषण में लोगों की निर्भरता सुविधाओं पर बढ़ती हुई पाई गई। असमानता और मतदाता के गलत व्यवहार की बढ़ती संभावना का भी आंकलन किया गया। अध्ययन में यह भी पाया गया कि, इन मुफ्त सुविधाओं और योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओ में कटौती की जाती है। दीर्घकालिन विकास में बाधा आती है और आत्मनिर्भरता के साथ रोजगार सृजन में भी कमी होती है।

रिकेश बैरागी

मुफ्त सुविधाओं को देने के लिए सरकार को अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए सरकारों को कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जिससे क्रेडीट रेटींग में गिरावट की संभावना रहती है। पंजाब में मुफ्त सुविधाओं की राजनीति इसका जीता जागता उदाहरण है, और तमीलनाडु उसी उदाहरण की श्रेणी में है।

सीधी बात समझने की आवश्यकता है कि, चुनावी वादों में मुफ्त सुविधाओं से अल्पकालिन लाभ संभावित है। लेकिन यह लोभ, लालच है उसका सीधा अर्थ है नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता का प्रभावित होना है। प्रश्न यह भी है कि, मुफ्त सुविधाओं से देश की गरीबी मिटाने के प्रयास सार्थक सिद्ध हो सकते है या वह सिर्फ राजनीति दलों की चाल है।

संपादकीय

फर्जी लेबल हैं जीवन से खिलवाड़

भारत में सामान्यतरू उत्पादों पर गुणवत्ता व उपयोग-तिथि के दावों के बावजूद उसके सेहत से जुड़े सरोकार सवालों के घेरे में रहे हैं। यह आम धारणा बनी हुई है कि कुछ लोग मुनाफे के लिए सामान की एक्सपाइरी डेट दर्ज करने में हेरफेर करने तक से नहीं चूकते। यह भी विश्वास से नहीं कहा जा सकता है कि सामान में शामिल घटकों का विवरण ईमानदारी से लेबल पर दर्ज किया गया हो। गाहे-बगाहे मीडिया व उपभोक्ता अदालतों में ऐसे मामलों की गूंज रहती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से संवेदनशील लोगों के जीवन पर सही लेबलिंग से आंच नहीं आ सकती। इसी के मद्देनजर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा कई खाद्य कंपनियों को गुमराह करने वाले ट्रेड नाम के इस्तेमाल और सेहत से जुड़े दावों के लिए नोटिस जारी करना, निश्चय ही एक स्वागतयोग्य कदम है। अक्सर प्रतिष्ठित उत्पाद वाली कंपनियों के लेबल लगाकर हल्के सामान बेचने के मामले भी उजागर होते हैं। हकीकत है कि आकर्षक पैकेजिंग के जरिये उत्पाद की न्यूट्रिशन से जुड़ी जानकारी को पार्श्व में डाल दिया जाता है। विडंबना यह है कि देश में ऐसा नियामक तंत्र विकसित नहीं हो पाया है जो लगातार जनहित में खाद्य उत्पादों की जांच-पड़ताल कर सके। निश्चित रूप से रेगुलेटरी संस्था की निगरानी सिर्फ कभी-कभार नोटिस जारी करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इस तरह की कार्रवाई कुछ समय के लिए तो सुर्खियां बनती हैं लेकिन फिर लोगों को इसकी याद कम ही रह जाती है। इस तरह की पहल को ग्राहकों की सुरक्षा में पारदर्शिता, जवाबदेही और जागरूकता पर आधारित लगातार चलने वाले एक राष्ट्रीय मिशन का रूप दिया जा सकता है। निश्चित रूप से लाखों भारतीयों के लिए खाने की चीजों पर लेबलिंग सेहत से जुड़ा मामला है। मसलन कशेरुक रोग से पीड़ित लोग ग्लूटेन से बचने के लिए लेबलिंग पर लिखी जानकारी पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि यह उनकी आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है।

निसंदेह, कई एलर्जी व रोगों से जूझने वाले लोगों को कुछ उत्पादों में मौजूद पदार्थों की वजह से लंबे समय तक रहने वाली परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन विडंबना यह है कि उत्पादों के लेबल पर आधी-अधूरी, अस्पष्ट जानकारी ही दी जाती है। अक्सर उत्पादों पर हेल्दी, नेचुरल और आयुर्वेद पद्धति पर आधारित जैसे लुभावने शब्दों का इस्तेमाल करके ग्राहकों को भ्रमित किया जाता है, जिससे उपभोक्ता असमंजस की स्थिति में पड़ आते हैं। मधुमेह, एलर्जी और खानपान से जुड़े दूसरे परहेजों में अस्पष्ट व गलत जानकारी हानिकारक हो सकती है। उत्पादकों की ईमानदारी व उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर भरोसा करना ग्राहकों के लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे-जैसे भारतीय समाज में पैकेट बंद खाद्य पदार्थों का प्रचलन तेजी से बढ़ा है, देश में एक मजबूत नियामक ढांचे की सख्त आवश्यकता महसूस की जा रही है। दरअसल, देखने में आता है कि छोटे दुकानदार अपने नुकसान को बचाने के लिए उसका बोझ ग्राहकों पर डाल देते हैं। एक प्रतिबद्ध नैतिकता का अभाव इस मुनाफे के कारोबार में अक्सर नजर आता है। निस्संदेह, किसी उत्पाद के पैकेट में उल्लेखित जानकारी ग्राहक के समझने के लिए आसान होनी चाहिए। साथ ही बिना तथ्य व तार्किकता के सेहत से जुड़े दावे करने वाले उत्पादकों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। इसके लिये जरूरी है कि समय-समय पर इन उत्पादों की उत्पादन प्रक्रिया की औचक निगरानी व पड़ताल होनी चाहिए। साथ ही बार-बार नियम तोड़ने पर कड़े जुर्माने का प्रावधान भी होना जरूरी है। देश में कोशिश हो कि उपभोक्ता जागरूकता अभियान को सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति का हिस्सा बनाया जाए। इस अभियान में स्कूलों, हेल्थकेयर संस्थानों और विभिन्न मीडिया समूहों को आम लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए कि किसी उत्पाद में दर्ज न्यूट्रिशन लेबल को कैसे समझें। कैसे भ्रमित करने वाले दावों की पड़ताल करें। साथ ही कैसे वे सेहत के अनुकूल उत्पादों के विकल्प का चयन कर सकें। निश्चित रूप से एक जागरूक उपभोक्ता ही अनैतिक मार्केटिंग के खिलाफ बचाव की राह दिखा सकता है। खाद्य उत्पाद से जुड़े कारोबारियों को कानून के बजाय नैतिक दायित्वों के निर्वहन से कारोबार में शुचिता को बनाये रखनी चाहिए।

अदालती फैसले के सामाजिक संकेतों को समझें

कुछ फैसले अदालतों के रिकॉर्ड में दर्ज होकर खत्म नहीं होते। वे समाज की सोच में प्रवेश करते हैं और उन मान्यताओं को चुनौती देते हैं जिन्हें लंबे समय से सामान्य मान लिया गया हो। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला, जिसमें सड़क दुर्घटना में एक गृहिणी की मृत्यु के मामले में घरेलू श्रम के आर्थिक मूल्य को स्वीकार किया गया, ऐसा ही फैसला है। पहली नजर में यह मामला महज मुआवजे के निर्धारण का लग सकता है, लेकिन इसकी असली गूंज उससे कहीं आगे जाती है। यह उस सामाजिक सोच पर सवाल उठाता है, जिसने घर के भीतर होने वाले महिलाओं के श्रम को प्रतिष्ठा नहीं दी।

अदालत ने माना कि गृहिणी सही मायने में 'होममेकर' है। उसका श्रम उत्पादक है, उसका योगदान वास्तविक है और उसकी अनुपस्थिति का असर केवल भावनात्मक नहीं, आर्थिक और संरचनात्मक भी होता है। सवाल यह नहीं है कि अदालत ने घरेलू श्रम का आर्थिक मूल्य किस आधार पर तय किया। प्रश्न यह है कि जिस श्रम पर करोड़ों परिवार टिके हुए हैं, उसे श्रम मानने में हमें इतना समय क्यों लगा।

भारत में परिवार को एक संस्था के रूप में देखा गया है। उसकी स्थिरता, उसकी सामाजिक भूमिका और सांस्कृतिक महत्व पर लगातार बात होती रही है। लेकिन इस स्थिरता को बनाए रखने वाले श्रम पर उतनी गंभीर चर्चा नहीं हुई। घर चलाना केवल खाना बनाने तक सीमित नहीं होता। यह समय प्रबंधन, संसाधनों का संतुलन, बच्चों की परवरिश, बुजुर्गों की देखभाल, सामाजिक संबंधों का निर्वाह और परिवार की भावनात्मक संरचना को संभालने की निरंतर प्रक्रिया है। घर के भीतर होने वाला यह श्रम इसलिए अदृश्य हो जाता है क्योंकि वह बाजार के बाहर होता है। जिस काम के लिए बाहर किसी को नियुक्त किया जाए तो उसका भुगतान तय होता है, वही काम जब घर के भीतर किया जाता है तो उसे जिम्मेदारी, प्रेम या संस्कार का विस्तार मान लिया जाता है। यहां समाज को अपने भीतर झांकने की जरूरत है। हमारे यहां लंबे समय तक एक सामान्य वाक्य चलता रहा, 'वह काम नहीं करती, घर संभालती है।' कथन के भीतर एक गहरी सामाजिक संरचना छिपी है।

सम्मान और मूल्य एक चीज नहीं हैं। सम्मान भावनात्मक हो सकता है, लेकिन मूल्य सामाजिक स्वीकृति का आधार बनता है। जिस योगदान को मूल्य नहीं मिलता, धीरे-धीरे उसकी भूमिका को स्वाभाविक मान लिया जाता है। फिर उसके पीछे का श्रम, समय और कौशल दिखाई देना बंद हो जाता है। विडंबना यह है कि परिवार की पूरी व्यवस्था को संभालने वाला व्यक्ति अक्सर आर्थिक परिभाषाओं में 'निर्भर' माना जाता रहा। यह विरोधाभास सोच का भी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी सोच को चुनौती देता है। निस्संदेह, अदालत के फैसले ने नुकसान की परिभाषा को नया अर्थ दिया।

अब तक जब किसी नौकरीपेशा व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसकी आय को परिवार की आर्थिक क्षति का आधार माना जाता था। लेकिन गृहिणी की मृत्यु के मामलों में यह तर्क दिया जाता रहा है कि उसकी प्रत्यक्ष आय नहीं थी, इसलिए आर्थिक नुकसान सीमित माना जाता है। वास्तव में किसी होममेकर की अनुपस्थिति केवल एक सदस्य की अनुपस्थिति नहीं होती। उसके साथ घर की पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है। बच्चों की दिनचर्या बदलती है, देखभाल की प्रणाली बदलती है, घरेलू खर्च का स्वरूप बदलता है और परिवार की कार्यक्षमता पर असर पड़ता है।

यह फैसला बताता है कि हर वह काम जो वेतन में नहीं बदलता, वह मूल्यहीन नहीं होता। हालांकि, इस फैसले को महिलाओं के लिए वेतन की बहस तक सीमित करना भी उचित नहीं होगा। आज जब अथ व्यवस्था, उत्पादकता और कार्यबल भागीदारी जैसे विषय चर्चा में हैं, तब यह स्वीकार करना जरूरी है कि सामाजिक पुनरुत्पादन, यानी परिवार का निर्माण और संचालन भी किसी अर्थव्यवस्था की बुनियादी शर्त है।

दिनेश भारद्वाज

घर मनुष्य निर्माण की पहली संस्था होता है। यदि उस संस्था को चलाने वाले श्रम को लगातार अदृश्य रखा जाएगा तो बराबरी और सम्मान पर आधारित समाज की कल्पना अधूरी रहेगी। यह फैसला समाज को संबोधित करता है कि क्या हम अपने घरों में श्रम की बराबरी को समझते हैं?

इन प्रश्नों के उत्तर अदालत नहीं दे सकती। समाज को खुद तय करना होगा कि वह इस फैसले को केवल मुआवजे के मामले का निर्णय मानता है या अपने समय के एक महत्वपूर्ण सामाजिक संकेत की तरह पढ़ता है। क्योंकि किसी होममेकर का मूल्य उस दिन तय नहीं होना चाहिए जब उसकी अनुपस्थिति दर्ज की जाए। उसका मूल्य उस दिन पहचाना जाना चाहिए जब वह हर दिन बिना किसी पदनाम, वेतन और औपचारिक पहचान के घर को चलाने के लिए उपस्थित होती है।

किसी समाज की परिपक्वता इस बात से नहीं मापी जाती कि वह श्रम का कितना भुगतान करता है। यह फैसला उन महिलाओं के लिए सामाजिक स्वीकृति है, जिनकी उपस्थिति से घर केवल चलता नहीं बल्कि आकार लेता है। और शायद इसकी सबसे बड़ी शक्ति भी यही है। अदालत ने अपने हिस्से का निर्णय दे दिया है। अब समाज को अपने हिस्से का उत्तर देना है।

महिला सुरक्षा, जवाबदेही और न्याय के सवाल

कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में नाबालिग दलित लड़की के साथ डॉक्टर द्वारा किए गए कथित दुराचार की घटना ने प्रदेश को झकझोर दिया। घटना के तुरंत बाद जनवादी महिला समिति और अन्य सामाजिक संगठनों ने कुरुक्षेत्र समेत विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, पीड़िता के पुनर्वास तथा राज्य महिला आयोग की जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की।

उल्लेखनीय है कि आरोपी चिकित्सक पर विगत में भी यौन शोषण से जुड़े कई आरोप लगाए जाने की बात कही जाती है। वर्ष 2008 में कुरुक्षेत्र के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए आई एक कंप्यूटर साइंस छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। अस्पताल प्रशासन द्वारा जांच के लिए एक समिति गठित किए जाने की जानकारी सामने आई थी। हालांकि उस समय उन्हें न तो पद से हटाया गया और न ही स्थानांतरित किया गया। बाद में मामले में कथित रूप से जांच प्रक्रिया और बयान दर्ज होने के आधार पर क्लोजर रिपोर्ट तैयार होने की बात कही गई।

इसके अलावा वर्ष 2017 में भी एक दलित महिला द्वारा अस्पताल परिसर में दुराचार का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराने और मामला अदालत तक पहुंचने की बात सामने आई। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौते की स्थिति बनने की बात सामने आई।

वर्तमान घटनाक्रम में राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन 6 जून को कुरुक्षेत्र पहुंचीं और पूरे मामले की समीक्षा की। सभी जानते हैं कि नर्सों का कार्य डॉक्टरों की निगरानी करना नहीं, बल्कि मरीजों की सेवा करना है। अस्पताल के भीतर नर्सों को लाइन में खड़ा कर वीडियो रिकॉर्डिंग कराने और कथित रूप से विवादस्पद टिप्पणियां करने को लेकर असंतोष उभरा। नर्सों ने अपने सम्मान और गरिमा से जुड़ी टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए चेयरपर्सन से इस्तीफे और सार्वजनिक माफी की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया।

नर्सों के आंदोलन के बाद जब उन्होंने पद से त्यागपत्र दिया और सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी, तब कथित रूप से आरोपी डॉक्टर और उन्हें संरक्षण देने वाली लॉबी द्वारा सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से नर्सों के खिलाफ अभियान चलाया जाने लगा। ऐसे में यह अभियान यौन हिंसा के आरोपी और उनके समर्थकों को बचाने की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जनवादी महिला समिति के नेतृत्व में 5 जून को कुरुक्षेत्र में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। महिला नेतृत्व अस्पताल में पीड़ित बच्ची से भी मिला। उसके बाद ही राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा अगले दिन कुरुक्षेत्र पहुंचीं। वहां उनके व्यवहार को लेकर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं, जिन्हें आयोग की गरिमा के अनुरूप नहीं माना गया। आरोप है कि उन्होंने आरोपी के बजाय नर्सिंग स्टाफ पर ही दोष मढ़ने की कोशिश की।

सवाल यह है कि चिकित्सक के रूप में कार्यरत उस व्यक्ति पर पहले भी ऐसे गंभीर आरोप लगते रहे हैं, फिर भी सेवानिवृत्ति के बाद उसे दोबारा नियुक्ति कैसे दी गई, इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? यह प्रश्न प्रशासनिक और निर्णय प्रक्रिया की जवाबदेही की ओर संकेत करता है। यह आशंका भी जताई जा रही है कि उच्च स्तर पर किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संरक्षण से वह कानून की सख्ती से बचता रहा। ऐसे गंभीर आरोपों के बावजूद उसके खिलाफ प्रभावी दंडात्मक कदम नहीं उठाए गए।

डॉ. जगमति सांगवान

महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए गठित संवैधानिक आयोग की अध्यक्ष होने के बावजूद, यदि सार्वजनिक रूप से नर्सिंग कर्मचारियों के साथ अनुचित व्यवहार और भाषा के प्रयोग के आरोप सामने आते हैं, तो इसे गंभीर आपत्ति के रूप में देखा जाता है। ऐसे मामलों में अपेक्षा की जाती है कि वे अस्पताल के प्रशासनिक कार्यालय में बैठकर औपचारिक तरीके से जानकारी प्राप्त करतीं। साथ ही सरकार से सवाल उठातीं कि संबंधित डॉक्टर की पुनर्नियुक्ति कैसे हुई। पूरे प्रकरण को लेकर चर्चा होती रही है कि कहीं यह प्रभावशाली राजनीतिक संरचना से जुड़े दबावों का परिणाम तो नहीं है।

सवाल यह भी है कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए बनी संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका क्या हो? यह सुनिश्चित कैसे किया जाए कि उनके पदों पर बैठे व्यक्ति स्वयं असुरक्षा का कारण न बनें। विभिन्न मामलों से जुड़े प्रकरण या कुरुक्षेत्र अस्पताल में 15 वर्षीय दलित लड़की के कथित यौन शोषणकृने यह सवाल और गंभीर कर दिया है कि क्या आरोपियों को कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संरक्षण मिलता रहा है। ऐसी घटनाओं का सामाजिक माहौल और सुरक्षा व्यवस्था पर गहरा असर पड़ता है। सरकार से अपेक्षा है कि दागी डॉक्टर की पुनर्नियुक्ति की उच्चस्तरीय-निष्पक्ष जांच हो, जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

मानवता ने चुकाई महत्वाकांक्षी युद्धों की कीमत

पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से विश्व अलग-अलग क्षेत्रों में युद्ध की विभीषिका झेल रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध? के चलते दोनों देशों की संपत्ति और विश्व आपूर्ति शृंखला को नुकसान हुआ। दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई और श्रम शक्ति का विस्थापन हुआ। लेकिन लड़ाई समाप्त होने का नाम नहीं ले रही।

पश्चिमी एशिया में अमेरिका, इस्राइल और ईरान के बीच जारी तनाव और अस्थिर संघर्ष, भले ही टलने की स्थिति में दिखे, लेकिन यह मानवता के लिए गंभीर क्षति पहुंचा रहा है। साथ ही चीन-ताइवान तनाव से एक और वैश्विक युद्ध का खतरा बढ़ता दिखता है। यदि यह संघर्ष भारत की सीमाओं तक पहुंचा, तो न केवल विश्व अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, बल्कि भारत भी तमाम आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सकता है।

अमेरिका-ईरान युद्ध से यूं तो पूरी दुनिया प्रभावित है, लेकिन विकासशील अर्थव्यवस्थाएं गहरे तक प्रभावित हो रही हैं। यह युद्ध 28 फरवरी को अमेरिका द्वारा खाड़ी स्थित ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने और संवर्धित यूरेनियम पर कब्जा करने के कथित लक्ष्य के साथ शुरू हुआ। वास्तव में इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का युद्ध में कूदने का उद्देश्य अपनी राजनीतिक सुरक्षा था। अमेरिका ने अपनी शक्ति पर गुमान करते हुए युद्ध छेड़ा, लेकिन इसके परिणामस्वरूप संघर्ष की विभीषिका से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई।

इस संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि अमेरिका-ईरान युद्ध में 14 देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो गए, क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे स्थित थे। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। दो महीने बाद शांति वार्ता शुरू हुई, लेकिन दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार नहीं थे। अमेरिका संवर्धित यूरेनियम पर कब्जा और होर्मुज मार्ग खुलवाना चाहता है, जबकि ईरान के फ्रीज खातों को खोलने और प्रतिबंध हटाने पर सहमति नहीं दे रहा था।

दूसरी ओर, ईरान ने होर्मुज के मुहाने पर नाकाबंदी कर दी है, जिससे तेल और गैस के टैंकर अटक गए हैं। अमेरिका भी ओमान की खाड़ी में नाकाबंदी कर रहा है। इससे दुनिया भर में कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और उनसे बनने वाले उत्पादों की आपूर्ति का संकट पैदा हुआ है, जिससे तमाम देशों में महंगाई और ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया है।

आर्थिक विश्लेषक कहते हैं कि इस युद्ध? के कारण दुनिया को इस समय तक अनुमानित 474 लाख करोड़ रुपये तक का नुकसान हो चुका है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन चेताता है कि अगर यूं ही ऊर्जा आपूर्ति बाधित रही तो पूरी दुनिया की जीडीपी घट जाएगी और रोजगार के अवसर समाप्त हो जाएंगे।

ईरान की परमाणु शक्ति, होर्मुज मार्ग, फ्रीज की गई संपत्तियां और लेबनान में हिज्बुल्लाह से जुड़े मुद्दे शांति स्थापना में प्रमुख बाधाएं हैं। यद्यपि अमेरिका और ईरान ने युद्धविराम बढ़ाया था, फिर भी परमाणु कार्यक्रम और फ्रीज फंडों को लेकर दोनों के मतभेद लंबे समय तक बने रहे। इन विवादों के कारण संघर्ष पूरी तरह समाप्त नहीं हो पा रहा था।

विश्व की शक्तियों को समझना चाहिए कि युद्ध? को लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। अमेरिकी संसद बार-बार कहती रही है कि यह युद्ध? तुरंत बंद होना चाहिए लेकिन ट्रम्प अपनी विजेता की छवि बनाकर ही इस युद्ध? से निकलना चाह रहे थे, जो तत्काल संभव नजर नहीं आता था।

ईरान ने अमेरिका जैसी महाशक्ति और इस्राइल की एकजुटता से मुश्किल लड़ाई लड़ी है, लेकिन अमेरिका का लगातार प्रतिरोध किया है। किसी भी समाधान के लिए दोनों पक्षों को लचीलापन दिखाना चाहिए, ताकि युद्ध की विभीषिका खत्म हो। तभी विश्व की आपूर्ति श्रृंखला को सामान्य बनाया जा सकता है।

सुरेश सेठ

यह भी हकीकत है कि पाकिस्तान और कतर के बैक-चौनल प्रयास तक अमेरिकादृईरान टकराव का समाधान समय रहते खत्म कर पाये। जिससे काफी समय तक सीमित युद्ध और होर्मुज नाकाबंदी जारी रही। जिसके कारण दुनिया आर्थिक संकट, महंगे ईंधन और ऊर्जा की कमी जैसी समस्याओं का सामना करती रही। परिणामस्वरूप, वैश्विक स्तर पर आर्थिक अस्थिरता बढ़ती रही ।

वहीं दूसरी ओर आशंका जतायी जा रही है कि इस्राइलदृहिज्बुल्लाह की झड़पें लेबनान में बड़े युद्ध का रूप ले सकती हैं। जिसका ईरान लगातार विरोध करता रहा है। यह मुद्दा भी समझौते होने में बाधक बना रहा है।

युद्ध के चलते स्थिति इतनी गंभीर है कि 14 देशों का एयरस्पेस बंद हो गया है, हजारों उड़ानें रद्द या डाइवर्ट हुई हैं, और ईंधन की कीमतें 130 प्रतिशत बढ़ गई हैं। खाड़ी और भारत के यात्रा रूट पर टिकटों की कीमतें भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ी हैं। आर्थिक संकट आम आदमी की जीवनशैली पर भारी पड़ रहा है और विकास के लक्ष्य बेअसर हो रहे हैं। इस बीच, हथियार व्यापार और युद्धरत देशों की राजनीति मानवता और शांति के मूल्यों को भूलती नजर आ रही है। इस समय शांति और अहिंसा के संदेश कोरे भाषण लगने लगे हैं।

नामांकन निरस्त मामले को लेकर जिले में बवाल

माही की गूंज, मंदसौर।

मध्य प्रदेश से राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के विरोध में मंदसौर में युवक कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कार्यालय से भाजपा कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच रास्ते में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प, धक्का-मुक्की और खींचतान की स्थिति बन गई।

सुबह बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कार्यालय पर एकत्र हुए। यहां से वे रैली के रूप में भाजपा कार्यालय की ओर बढ़े। गांधी चौराहे और बालाजी मंदिर के बीच पुलिस ने पहले से बैरिकेडिंग कर सुरक्षा घेरा बना रखा था। जैसे ही कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के पास पहुंचे, उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की। कई कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसके चलते मौके पर तनावपूर्ण माहौल बन गया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने पहले समझाइश दी, लेकिन जब कार्यकर्ता नहीं माने तो फायर ब्रिगेड के जरिए पानी की बौछार की गई। इसके बाद भी प्रदर्शन जारी रहने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया। घटना में कुछ कार्यकर्ताओं के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है।

एक घंटे तक चली पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच रस्साकशी

प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच करीब एक घंटे तक आमना-सामना चलता रहा। पानी की तेज बौछारों के बावजूद प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए और विरोध जारी रखा। हालात नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। कई कार्यकर्ताओं को पुलिसकर्मियों ने पकड़कर हटाया, जबकि कुछ को उठाकर पुलिस वाहनों तक ले जाया गया। इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार

प्रदर्शन के बाद पुलिस ने 13 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में दुर्गाशंकर धाकड़, राघव सिंह शक्तावत, तरुण खींची, सावन मकवाना, वर्षा, मुकेश धनगर, ऋतिक मालवीय, दुर्गेश पवार, हरिओम बैरागी, योगेंद्र गौड, ओमप्रकाश, अरबाज मंसूरी और एक अन्य कार्यकर्ता शामिल हैं। वहीं, कार्यकर्ता सम्यक जैन के घायल होने की जानकारी भी सामने आई है।

कांग्रेस का आरोप-लोकतांत्रिक विरोध को दबाया गया

जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर ने पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, ष्युवक कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ता शांतिपूर्ण एवं गांधीवादी तरीके से भाजपा कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे। लेकिन पुलिस ने भाजपा के दबाव में आकर लाठीचार्ज किया और कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया। कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखती है और शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रही थी।

बिना अनुमति हो रहा था प्रदर्शन

वहीं, सीएसपी जितेंद्र भास्कर ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बिना अनुमति भाजपा कार्यालय घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने और समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने कहा, ष्कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले पानी की बौछार की गई। इसके बाद कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। कुल 10 से 12 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है।

भारी पुलिस बल रहा तैनात

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शहर में 5 से 6 थानों का पुलिस बल तैनात किया गया था। पूरे घटनाक्रम के दौरान प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त बल भी मौजूद रखा गया। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने के विरोध में हुआ यह प्रदर्शन राजनीतिक रूप से गर्माए माहौल का संकेत माना जा रहा है। घटना के बाद कांग्रेस ने आंदोलन तेज करने के संकेत दिए हैं, जबकि प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने को अपनी प्राथमिकता बताया है।

दिल दहला देने वाली वारदात

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले से एक बेहद सनसनीखेज और दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। यह वारदात 31 दिसंबर 2025 की रात करीब 8 बजे शहर के गोल चौराहा क्षेत्र में हुई, जहां एक सोना कारोबारी दंपती पर बेरहमी से जानलेवा हमला किया गया।

आरोपी विकास सोनी पीड़ित परिवार के घर पहुंचा था और सामान्य बातचीत के दौरान उसने पहले चाय पी और बिस्किट भी खाए। इसी दौरान माहौल सामान्य दिख रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसने अचानक खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। आरोप है कि विकास सोनी ने सोना कारोबारी दिलीप जैन पर चाकू से 11 बार हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही हालत गंभीर हो गई। इसके बाद उसने उनकी पत्नी रेखा जैन पर भी बर्बर हमला करते हुए 30 से अधिक वार किए। इस हमले के बाद पूरा घर खून से सन्नाटे में बदल गया और इलाके में हड़कंप मच गया।

वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने शोर सुनकर मौके पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन तब तक दोनों पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी गई, जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

हालांकि, डॉक्टरों के मुताबिक, हमले की गंभीरता को देखते हुए दोनों की हालत बेहद नाजुक बताई गई। पुलिस ने घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू कर दी है और पूरे मामले की हर एंगल से पड़ताल की जा रही है।

प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि यह वारदात किसी व्यक्तिगत रंजिश या विवाद का नतीजा हो सकती है, हालांकि पुलिस अभी सभी पहलुओं की जांच कर रही है। घटनास्थल से सबूत जुटाए गए हैं और फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। इस घटना ने पूरे मंदसौर क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय लोगों ने इस तरह की हिंसक वारदात पर गहरी चिंता जताई है और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। कुल मिलाकर, मंदसौर की यह घटना एक बेहद क्रूर और चौंकाने वाली वारदात है, जिसने एक कारोबारी परिवार की जिंदगी को तबाह कर दिया और पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है।

8 औद्योगिक प्लॉटों की ई-बिडिंग शुरू

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले के जग्गाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में निवेश और औद्योगिक विस्तार के नए अवसर खुल गए हैं। मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) ने यहां आठ नए औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन के लिए ई-बिडिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है।इससे क्षेत्र में नए उद्योगों की स्थापना और रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ गई हैं।

जग्गाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में पहले उपलब्ध सभी भूखंड आवंटित हो चुके थे, जिसके बाद उद्योग स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों की मांग लगातार बनी हुई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए एमपीआईडीसी ने अतिरिक्त प्लॉटों को विकसित कर पुनः आवंटन प्रक्रिया शुरू की है।

निवेशकों के लिए बड़ा मौका

औद्योगिक विकास निगम के अधिकारियों के अनुसार, यह ई-बिडिंग प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा रही है। इसमें देशभर के निवेशक भाग ले सकते हैं। इन प्लॉटों का उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना और स्थानीय स्तर पर औद्योगिक गतिविधियों को गति देना है।

अधिकारियों ने बताया कि जग्गाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र पहले से ही कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं के लिहाज से निवेशकों के लिए आकर्षक स्थान माना जाता है। यहां सड़क, बिजली, पानी और अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे उद्योगों की स्थापना में आसानी होती है।

रोजगार के नए अवसर

नए औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन प्लॉटों पर उत्पादन इकाइयां स्थापित होती हैं तो आसपास के युवाओं को रोजगार मिलेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

स्थानीय व्यापारियों और उद्यमियों ने इस पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि औद्योगिक विस्तार से न केवल निवेश बढ़ेगा बल्कि छोटे व्यवसायों को भी अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

पहले से पूरी हो चुकी थी भूमि

एमपीआईडीसी के अनुसार, जग्गाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में पूर्व में सभी भूखंड आवंटित हो चुके थे, लेकिन बढ़ती मांग और निवेश की रुचि को देखते हुए नए प्लॉट विकसित किए गए हैं। इनका उद्देश्य उन उद्योगपतियों को अवसर देना है जो लंबे समय से यहां निवेश की प्रतीक्षा कर रहे थे।

पारदर्शी प्रक्रिया पर जोर

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूरी ई-बिडिंग प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होगी, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना न रहे। इच्छुक निवेशक निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं।

क्षेत्रीय विकास की दिशा में कदम

मंदसौर जिले में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक उद्योग यहां स्थापित हों और जिले को औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जा सके।

इस नई ई-बिडिंग प्रक्रिया के शुरू होने के साथ ही जग्गाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में एक बार फिर निवेश की रफ्तार तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है।

दोस्ती की आड़ में दोस्त की बहन के साथ घिनौना काम

माही की गूंज, रतलाम।

जिले में जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। पीड़िता के साथ ये सब कुछ उसके भाई के दोस्त ने किया है। उसने बार-बार पीड़िता के साथ रेप किया। साथ ही दो बार उसका गर्भपात करवाया। इसके बाद धर्म परिवर्तन करवाकर निकाह किया है। अब उसका एक बच्चा है लेकिन पीड़िता के साथ आए दिन मारपीट करता है।

डीडी नगर क्षेत्र में रहती है पीड़िता

दरअसल, 19 वर्षीय पीड़िता रतलाम के डीडी नगर क्षेत्र में रहती है। उसने अपने भाई के दोस्त समीर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। आरोपी है कि करीब तीन साल पहले आरोपी समीर ने उसके साथ रेप किया था। फिर चाकू की नोक पर उसने बार-बार ऐसा किया है।

अबॉर्शन करवाया

आरोपी ने पीड़िता को दो बार प्रेग्नेंट किया। साथ ही उसका अबॉर्शन भी करवाया। आरोपी समीर रामरहीम नगर का रहने वाला है। पीड़िता के भाई से दोस्ती की वजह से उसका घर आना जाना लगा रहता था। इसी पहचान की वजह से आरोपी ने पीड़िता से नजदीकी बढ़ाई।

अपने घर ले जाकर किया दुष्कर्म

पीड़िता के साथ आरोपी ने पहली बार 2023 मेंदुष्कर्म किया। उस समय पीड़िता 11वीं की छात्रा थी। पहले आरोपी ने पीड़िता को अपने जाल में फंसाया। इसके बाद अपने रामरहीम नगर स्थित घर ले गया, जहां उसके साथ गलत किया।

अबॉर्शन करवा दिया

इस दौरान पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई। यह पता चलते ही समीर ने उसे गर्भपात की गोलियां दे दीं। साथ ही पीड़िता को चाकू दिखाकर धमकाया कि किसी को कुछ बताया तो तुम्हें और तुम्हारे भाई को मार दूंगा। डर से युवती चुप रही। इस नाम पर समीर उसके साथ संबंध बनाता रहा। कुछ दिनों बाद पीड़िता दोबारा प्रेग्नेंट हो गई।

जबरदस्ती निकाह करवाया

पीड़िता के दोबारा प्रेग्नेंट होने पर समीर उसे डरा धमकाकर दूसरी जगह ले गया। वहां उससे जबरदस्ती निकाह किया। उस समय युवती नाबालिग ही थी। निकाह के बाद युवती को अपने घर लेकर चला गया। साथ ही परिजनों से मिलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी।

जान से मारने की धमकी देने लगा

इसके बाद युवती ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा अब नौ महीने का हो गया है। साथ ही समीर अब युवती के साथ मारपीट शुरू कर दी है। धमकी देता है कि मेरे पास तेरे जैसी बहुत हैं। ज्यादा कुछ करेगी तो जान से मारकर तुम्हें फेंक दूंगा।

युवती ने घरवालों को दी जानकारी

वहीं, टॉर्चर बढ़ने के बाद युवती ने अपने घरवालों को पूरी जानकारी दी। इसके बाद वह घर गई। लेकिन समीर ने उसके परिवार को भी धमकी दी। 8 जून को समीर ने युवती के साथ मारपीट की। इसके निशान उसके शरीर पर हैं।

बच्चे को छीनने की कोशिश की

10 जून को पीड़िता से समीर ने बच्चे को छीनने की कोशिश की। आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया। इसके बाद युवती के भाई को चाकू से गोदकर हत्या करने की धमकी दी। लगातार धमकियों से तंग आकर युवती ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

किसान नेता पर ब्लैकमेलिंग का केस

माही की गूंज, आगर/मालवा।

शाजापुर-देवास के पूर्व सांसद स्व. मनोहर ऊंटवाल की पुत्रवधू के नाम से डाली जा रही गिट्टी मशीन को अवैध बताकर भारतीय किसान यूनियन मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष पर डेढ़ लाख रुपये मांगने का आरोप लगा है। शिकायत पर पुलिस ने ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया।

पूर्व सांसद के पुत्र मनोज ऊंटवाल ने असावता में लीज पर भूमि लेकर उनकी पत्नी संगीता के नाम पर गिट्टी मशीन डलवा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक गुर्जर ने इसे अवैध बताते हुए कुछ ग्रामीणों के साथ आंदोलन किया था। रतलाम कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया।

मनोज ने चर्चा करने की बात कही तो उन्हें महिदपुर के गांव कल्लूखेड़ी के फंटे पर बुलाकर तीन लाख रुपये की मांग की। डेढ़ लाख रुपये में डील तय हो गई लेकिन मनोज ने ताल थाने में ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ शिकायत कर दी।

शिकायत के बाद पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने आरोपी पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। एफआईआर के बाद भारतीय किसान यूनियन मंच के प्रदेश अध्यक्ष देवसिंह गुर्जर ने तत्काल प्रभाव से आरोपी को उपाध्यक्ष पद से हटा दिया। बता दें कि आरोपी ने ईंट भट्टा संचालकों के खिलाफ भी आंदोलन किया था।

कलेक्टर को आतंकवादी, एसपी को गुंडा कहा, किसान का जनसुनवाई में हंगामा

माही की गूंज, शाजापुर।

सीमांकन विवाद से नाराज एक किसान ने मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर हंगामा किया। उसने कलेक्टर ऋजु बाफना को आतंकवादी और एसपी यशपालसिंह राजपूत को गुंडा तक कह दिया। किसान का हंगामा बढ़ता देख मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने लाठी दिखाकर धक्का देते हुए उसे कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर कर दिया।

शरद कुमार शर्मा निवासी पोलायकलां ने बताया कि उनकी भूमि सर्वे नंबर 4446ध्3 के सीमांकन में राजस्व अमले ने हेराफेरी की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2019 से अब तक कलेक्टर कार्यालय, संबंधित अधिकारियों और सीएम हेल्पलाइन पर लगभग 50 से 60 आवेदन दिए हैं।

लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनकी जमीन को जानबूझकर दूसरे किसान की भूमि बताया जा रहा है और सांठगांठ के चलते गलत सीमांकन किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने और एक नई टीम गठित कर फिर से सीमांकन कराने की मांग की है।

एसपी ने एएसआई को किया निलंबित

किसान शरद द्वारा कलेक्ट्रेट में कलेक्टर एसपी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने से ड्यूटी पर तैनात लालघाटी थाने के एएसआई महेश कुमार घुरे भी आक्रोशित हो गए। उन्होंने शरद को हड़काते हुए अपशब्द कह दिए।

जिसका वीडियो सोशल मीडिय पर वायरल हो गया। मामले में संज्ञान लेते हुए एसपी यशपालसिंह राजपूत ने एएसआइ घुरे के व्यवहार को अनुचित माना और मप्र सिविल सेवा नियम 1966 नियम के नौ के तहत कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है।

हंगामा कर रहा था

लालघाटी टीआई अजुर्नसिंह मुजाल्दे ने कहा कि, जनसुनवाई में पोलायकलां निवासी एक व्यक्ति हंगामा कर रहा था। अधिकारियों के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहा था। इसलिए पुलिसकर्मियों ने उसे समझाइश देकर कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर निकाला।

मार्ग निर्माण की मांग को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन

माही की गूंज, खंडवा।

खंडवा-मूंदी मार्ग के निर्माण और निविदा प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने की मांग को लेकर मंगलवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप प्रतिमा से कलेक्टर कार्यालय तक दंडवत यात्रा निकालकर शासन का ध्यान सड़क की समस्या की ओर आकर्षित किया।

यात्रा के समापन पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसमें मार्ग निर्माण कार्य को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई। दंडवत यात्रा का नेतृत्व एनएसयूआई कार्यकर्ता चंदनसिंह पंवार और मोंटी पंवार ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। इसके बाद कार्यकर्ता दादाजी धाम, संत सिंगाजी महाराज और भगवान ओंकारेश्वर का स्मरण करते हुए दंडवत यात्रा के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय पहुंचे।

ज्ञापन में बताया गया कि खंडवा-मूंदी मार्ग लंबे समय से जर्जर स्थिति में है। सड़क पर बने गड्ढों और खराब मार्ग के कारण प्रतिदिन हजारों लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका सबसे अधिक प्रभाव किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों पर पड़ रहा है।

एनएसयूआई ने मांग की कि मार्ग के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य के लिए तत्काल निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाए। संगठन का कहना है कि यह मार्ग क्षेत्र की प्रमुख संपर्क सड़क है, लेकिन लंबे समय से इसकी अनदेखी की जा रही है।

कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनता की समस्या अब गंभीर रूप ले चुकी है और शासन-प्रशासन को इस दिशा में त्वरित निर्णय लेना चाहिए। एनएसयूआई नेता चंदनसिंह पंवार ने कहा कि जब तक खंडवा-मूंदी मार्ग निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं होती, तब तक संगठन लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेगा। साथ ही जनप्रतिनिधियों और शासन से हस्तक्षेप कर शीघ्र निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की गई।

राष्ट्रपति के ओंकारेश्वर आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त

माही की गूंज, ओंकारेश्वर।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 18 और 19 जून को प्रस्तावित ओंकारेश्वर प्रवास को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है। कार्यक्रम स्थल, यात्रा मार्ग तथा आसपास के क्षेत्रों में बहुस्तरीय सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा कारणों से मानव रहित उड़ान यंत्रों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है तथा कई वस्तुओं को कार्यक्रम स्थल पर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

राष्ट्रपति के आगमन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास विशेष निगरानी रखी जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था के तहत कार्यक्रम स्थल के आसपास मानव रहित उड़ान यंत्र और उनसे जुड़े कैमरों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा चाकू, छुरी, ब्लेड सहित अन्य धारदार वस्तुएं, पानी की बोतलें, पाउच, लाइटर, माचिस, पटाखे तथा ज्वलनशील सामग्री भी प्रतिबंधित श्रेणी में रखी गई हैं। लाठी, डंडा, छाता, किसी भी प्रकार के औजार या हथियार, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा एवं अन्य नशीले पदार्थों को भी कार्यक्रम स्थल पर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे मोबाइल फोन के अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैग, झोले, ढके हुए सामान और कीमती वस्तुएं साथ न लाएं।

पुलिस विभाग ने श्रद्धालुओं और नागरिकों से सुरक्षा नियमों का पालन करने तथा जांच प्रक्रिया में सहयोग देने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि सभी के सहयोग से कार्यक्रम को सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जा सकेगा।

ब्राउन शुगर के साथ युवक गिरफ्तार

माही की गूंज, खरगोन।

बिस्टान क्षेत्र में पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब एक लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

बिस्टान थाना प्रभारी गुलाबसिंह रावत ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आंवली रोड पर एक युवक अवैध रूप से ब्राउन शुगर बेचने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस दल ने भीलट देव मंदिर के सामने घेराबंदी कर संजयनगर, खरगोन निवासी रिजवान पिता इकबाल पठान को पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके पास से 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई।

पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8ध्21 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। अब उसे न्यायालय से रिमांड पर लेकर ब्राउन शुगर के आपूर्तिकर्ताओं तथा तस्करी से जुड़े नेटवर्क के संबंध में पूछताछ की जाएगी।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि रिजवान के खिलाफ खरगोन कोतवाली में एनडीपीएस अधिनियम सहित 11 प्रकरण तथा बलकवाड़ा थाने में एक प्रकरण पहले से दर्ज है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित ठहराव मंजूर

माही की गूंज, खंडवा।

खंडवा जंक्शन के रेल यात्रियों को बड़ी सौगात मिली है। रेलवे ने पुणे-दानापुर अमृत भारत एक्सप्रेस (11431/11432) का खंडवा स्टेशन पर नियमित ठहराव स्वीकृत कर दिया है। इससे महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और बिहार के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।

यह रेलगाड़ी पहले विशेष रेलगाड़ी के रूप में संचालित की जा रही थी, लेकिन खंडवा स्टेशन पर इसका ठहराव नहीं था। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल द्वारा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर स्थायी संचालन और खंडवा में ठहराव की मांग किए जाने के बाद रेलवे मंत्रालय ने इसे मंजूरी प्रदान की है। मध्य रेल क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य मनोज सोनी ने इसे क्षेत्र की रेल सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय बताया है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 17 जून को पुणे से अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके नियमित संचालन की शुरुआत आगामी शनिवार से होगी। यह रेलगाड़ी पूरी तरह वातानुकूलित रहित होगी, जिसमें सामान्य और शयनयान श्रेणी के कुल 18 एलएचबी डिब्बे लगाए गए हैं। इससे सामान्य और शयनयान श्रेणी के यात्रियों को कम खर्च में लंबी दूरी की यात्रा की सुविधा मिलेगी।

पुणे से दानापुर जाने वाली रेलगाड़ी प्रत्येक शनिवार दोपहर साढे 3 बजे रवाना होकर रविवार सुबह 3 बजकर 55 मिनिट पर पहुंचेगी तथा सोमवार दोपहर 1:30 बजे दानापुर पहुंचेगी। वहीं दानापुर से पुणे जाने वाली रेलगाड़ी प्रत्येक सोमवार सुबह साढे 3 बजे रवाना होकर रात 10 बजकर 55 मिनिट पर खंडवा पहुंचेगी और मंगलवार सुबह 11 बजे पुणे पहुंचेगी।

यह रेलगाड़ी अपने मार्ग में पुणे, दौंड, अहमदनगर, मनमाड, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा सहित प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी। रोजगार, शिक्षा और व्यापार के लिए खंडवा क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग पुणे और बिहार की यात्रा करते हैं। नए ठहराव से यात्रियों को अतिरिक्त यात्रा सुविधा मिलेगी तथा खंडवा जंक्शन की रेल संपर्क व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। त्योहारी सीजन और भीड़भाड़ के समय भी यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा।

दरगाह मैदान में सांडों की भिड़ंत से मची अफरा-तफरी

माही की गूंज, बड़वानी। जिला मुख्यालय के पनवाड़ी मोहल्ला स्थित दरगाह मैदान में बुधवार दोपहर तीन सांडों के आपस में भिड़ जाने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सांडों की यह भिड़ंत करीब आधे घंटे तक चलती रही, जिससे क्षेत्र के लोगों में दहशत फैल गई। इस दौरान एक सांड पास बने पानी के टैंक में जा गिरा।

प्रत्यक्षदर्शियों अमजद और सद्दाम ने बताया कि दोपहर के समय तीन सांड अचानक मैदान में आकर आपस में भिड़ गए। सांडों की जोरदार टक्कर और आक्रामक व्यवहार को देखकर आसपास मौजूद लोग भयभीत हो गए और सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे।

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कुछ लोगों ने सांडों को अलग करने का प्रयास किया। उन पर पानी की बौछार भी डाली गई, लेकिन उनका आक्रामक व्यवहार जारी रहा। इसी दौरान एक सांड लड़ते हुए पानी के टैंक में गिर गया, जबकि अन्य दो सांड मैदान में ही भिड़ते रहे।

स्थानीय निवासी आसिफ ने बताया कि इसी तरह की घटना मंगलवार शाम को भी हुई थी। उस समय भी सांडों के बीच हुई भिड़ंत से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। घटना के दृश्य क्षेत्र में लगे निगरानी कैमरों में भी कैद हुए हैं।

लगातार दो दिनों से हो रही ऐसी घटनाओं के कारण मोहल्ले में भय का वातावरण बना हुआ है। लोगों का कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए घर से निकलना जोखिम भरा हो गया है। लंबे समय तक चले घटनाक्रम के चलते दरगाह मैदान और आसपास के क्षेत्र में आवाजाही भी प्रभावित रही।

मोहल्लेवासियों ने जिला प्रशासन और नगर पालिका से आवारा मवेशियों एवं सांडों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की है। उनका कहना है कि शहर में आवारा मवेशियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने समय रहते प्रभावी कार्रवाई किए जाने की मांग की है, ताकि किसी बड़े हादसे को रोका जा सके।

खारक नदी सूखने से 25 गांवों में गहराया जल संकट

माही की गूंज, खरगोन। भगवानपुरा क्षेत्र में खारक नदी पूरी तरह सूख जाने से नदी के निचले हिस्से में बसे 25 गांवों के सामने पेयजल संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने खड़ा जलाशय से पानी छोड़े जाने की मांग की है। बुधवार को जिला पंचायत उपाध्यक्ष बापू सिंह परिहार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उप जिला दंडाधिकारी वीरेंद्र कटारे से मुलाकात कर बांध से पानी छोड़े जाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि इससे प्रभावित गांवों के साथ-साथ खरगोन शहर को भी पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा।

मामले को गंभीरता से लेते हुए उप जिला दंडाधिकारी ने जल संसाधन विभाग की कार्यपालन यंत्री नीलम मेड़ा को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार खरगोन शहर के लिए आरक्षित पेयजल में से खारक बांध का एक चरण पहले ही छोड़ा जा चुका है। नगरपालिका और जल संसाधन विभाग के समन्वय से जल्द ही पानी का अगला चरण छोड़े जाने की संभावना है, जिससे राहत मिल सकेगी।

एसआईआर की तार्किकता और विरोध का प्रश्न

हाल ही में 'इंडिया' गठबंधन ने पांच-सूत्री प्रस्ताव पारित किया, जिसमें एक यह भी है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा जाएगा। यह गठबंधन 'एसआईआर' को 'वोट चोरी' मानता है। इसके कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 'एसआईआर' को लेकर चुनाव-आयोग को क्लीन-चिट दी है। प्रश्न है कि ऐसे में पत्र लिखने से मिलेगा क्या? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का कहना है, हम इसे 'वोट लूट' की कोशिश मानते हैं। भारत में घुसपैठ और नागरिकता रजिस्टर पिछले कई दशकों से बहस में हैं। यह बहस अब मतदाता सूची की बहस के साथ जुड़ गई है। 'एसआईआर' के देश में दो दौर हो चुके हैं और तीसरा शुरू हो गया है। पहला दौर मुख्यतः बिहार-केंद्रित था, जो जून से सितंबर, 2025 तक चला। 27 अक्तूबर से दूसरा दौर शुरू हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत, नौ राज्य और तीन केंद्र-शासित क्षेत्र शामिल थे।

गत 14 मई को निर्वाचन आयोग ने 'एसआईआर' के तीसरे दौर की भी घोषणा कर दी, जिसमें सोलह राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों को कवर किया गया है। इसके पूरा होने के बाद जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके साथ इस प्रक्रिया को बहस नए सिरे से शुरू होगी, जिसकी अनुगूंज संसद के मॉनसून सत्र में सुनाई पड़ेगी।

शिकायतें पहले दौर के पहले से ही शुरू हो गई थीं, पर पश्चिम बंगाल का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक गया। इस दौर में करीब 27 लाख वोटरों ने अपने नाम कटने को चुनौती दी। वे विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दे पाए, क्योंकि उनकी सुनवाई के लिए नियुक्त न्यायाधिकरण इस काम को पूरा नहीं कर पाए। यह काम चुनाव परिणाम आने के बाद भी चल ही रहा है। इन 27 लाख में 60 प्रतिशत से ज्यादा वोटरों की सूची में वापसी हो चुकी है और अंतिम समाचार मिलने तक न्यायाधिकरणों की प्रक्रिया जारी है। सवाल है कि उनकी सुनवाई के लिए नागरिक-प्रशासन पर राज्य सरकार ने भरोसा क्यों नहीं किया? चुनाव-आयोग की व्यवस्था है कि 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' के कारण कोई नाम 'अनमैप्ड' रह जाए, तो एक सूची में वर्णित दस्तावेजों में से कोई एक देकर अपने नाम को बनाए रखा जा सकता है। पर बंगाल में अविश्वास इतना गहरा था कि उस रास्ते पर जाने के बजाय लंबे रास्ते को अपनाया गया, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग वोट नहीं दे पाए।

कई तरह के सवाल सभी पक्षों से हैं। आयोग ने सूची के गहन-संशोधन के लिए पर्याप्त समय क्यों नहीं दिया? 2002 और 2003 की मतदाता सूचियों तक पहुंच पाना आसान काम नहीं है। पुरानी सूचियां जिस तरीके से बनाई गईं हैं, उनमें नाम, पते और वोटर कार्ड की संख्या खोजना खासा मुश्किल काम है। सामान्य नागरिक कागज-पत्रों के आदी नहीं हैं, उनके लिए यह प्रक्रिया आसान नहीं है।

देश की आम जनता दस्तावेजों की अभ्यस्त नहीं है। 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' को दूर करने के लिए दस्तावेजों को भी आसान बनाने की जरूरत है। वोटर को पुरानी सूची में अपना नाम खोजने में दिक्कत होती है। उसकी मदद की जानी चाहिए। आयोग की वेबसाइट को सरल बनाने और इस काम को करने वाले बीएलओ को बेहतर तरीके से तैयार करने की जरूरत भी है।

विरोधी-दलों ने इसे 'वोट चोरी' साबित करते हुए, राजनीतिक सवाल बनाया। चुनाव-आयोग, उसकी प्रक्रिया और ईवीएम की साख पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस बात को उन्हें सुप्रीम कोर्ट में साबित करना होगा। जब उन्हें विजय मिलती है, तब वे सवाल करते, क्यों नहीं करते? दिसंबर में लोकसभा में चुनाव-सुधारों पर हो रही बहस के दौरान एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, 'मैं इसी मशीन से चुनकर आई हूं, इसलिए मैं ईवीएम या वीवीपैट पर सवाल नहीं उठाऊंगी।'

सवाल हैं भी, तो उन्हें या तो आयोग और या फिर सुप्रीम कोर्ट में उठाना चाहिए। पर अब तो अदालती फैसलों पर भी संदेह पैदा किया जाता है। कहा जा रहा है कि आयोग को 'एसआईआर' कराने का अधिकार है ही नहीं। फिर मतदाता सूची में संशोधन या सुधार कैसे होगा? सोशल मीडिया के शोर ने स्थितियों को और बिगाड़ा है।

सुप्रीम कोर्ट ने अब 27 मई को याचिकाकर्ताओं के ज्यादातर तर्कों को मानने से इनकार कर दिया। वहीं चुनाव-आयोग के तर्कों को स्वीकार किया और उन्हें और स्पष्ट किया। हालांकि यह मामला बिहार में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के नियम को लागू करने से संबंधित था, लेकिन अदालत में विचारार्थ रखे गए मुद्दे और उसके निष्कर्ष देश भर की मतदाता सूचियों में नाम दर्ज कराने के अधिकार पर दूरगामी प्रभाव डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करे। यह बात भी निर्विवाद है कि जिस मतदाता सूची पर चुनाव आधारित हैं, वह सटीक और विश्वसनीय होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल ने, इन सिद्धांतों या मान्यताओं पर सवाल नहीं उठाया है। इस बात को भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि आयोग की भारत के लोकतांत्रिक विकास में अग्रणी भूमिका है। और यह भी कि बड़े पैमाने पर प्रवासन, तीव्र शहरीकरण, अवैध सीमा पार आवागमन, मृत्यु की सूचना न देने और प्रविष्टियों की पुनरावृत्ति को देखते हुए मतदाता सूची की समय-समय पर समीक्षा आवश्यक है। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है।

कमजोर मतदाताओं पर सबूत का बोझ डालना, एक बोझिल दस्तावेज-प्रणाली, समय-सीमा का कम होना और अपील प्रक्रिया के लिए समय-सीमा निर्धारित न करना सबसे ज्यादा चिंता के विषय हैं। अदालत के फैसले के बाद आयोग को असीमित प्रक्रियात्मक छूट मिल गई है। खासतौर से नागरिकता के मुद्दे पर भी, आयोग को मिली छूट को लेकर कुछ विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है।

प्रमोद जोशी

मतदाता सूची के पहले से देश में नागरिकता को लेकर बहस चल रही है। हालांकि, एसआईआर नागरिकता की परीक्षा नहीं है, लेकिन इसके माफर्त 'नागरिकता की सीमित जांच' का आधार बना सकता है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू होने के बाद से एक वर्ग के मन में संशय हैं। खबरें हैं कि बिहार और बंगाल की नई सरकारों ने घोषणा की है कि मतदाता सूची से जिनके नाम कट गए हैं, उन्हें सरकारी लाभ नहीं मिलेंगे।

अब मई के अंत में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों (डेमोग्राफिक चेंज) का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर हैं। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2025 को लाल किले के प्राचीर से 'घुसपैठियों' का उल्लेख करते हुए ऐसी समिति की आवश्यकता की घोषणा की थी।

ऐसे समय में जब 'घुसपैठिया' शब्द को लेकर भय का माहौल है, तब आम नागरिक के मन में चिंता के कारण बनते हैं। करीब-करीब ऐसा ही भय देशभर में काम कर रहे प्रवासी कामगारों के मन में है। बहुत से नहीं जानते कि उनके गृह-राज्य की सूची में उनका नाम है या नहीं। हाल में बंगाल में हुए चुनाव के समय प्रवासियों के बीच मची भगदड़ के पीछे एक भय यह भी था कि वोट नहीं डालेंगे, तो सुविधाएं कट जाएंगी।

सीएम के कार्यक्रम में मिला गंदा पानी

माही की गूंज, शाजापुर।

जिले के पोलायकलां तहसील क्षेत्र स्थित सेमलीधाम आश्रम में हाल ही में आयोजित वीआईपी कार्यक्रम के दौरान पीने के पानी की व्यवस्था में हुई गंभीर चूक ने एक बड़ा प्रशासनिक विवाद खड़ा कर दिया है। कार्यक्रम के दौरान वीआईपी और क्रू मेंबर्स को उपलब्ध कराए गए पानी के नमूने लैब जांच में फेल होने के बाद उज्जैन संभाग के आयुक्त आशीष सिंह ने शाजापुर के जिला आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही को कारण बताओ नोटिस (शो-कॉज) जारी किया है।

कलेक्टर पर साजिश का आरोप

इस मामले में आबकारी अधिकारी ने सीधे जिले के कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस पूरी कार्रवाई को अपने खिलाफ एक श्प्रायोजित साजिशश् करार दिया है। यह पूरा मामला 30 अप्रैल 2026 को आयोजित वीआईपी भ्रमण कार्यक्रम से जुड़ा है। आदेशानुसार, जिला आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही को हेलीपैड व्यवस्था, क्रू मेंबर्स और वीआईपी के भोजन व पेयजल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सैंपल जांच रिपोर्ट में अत्यधिक गंदलापन-मटमैला पाया गया। इस दौरान पानी की गुणवत्ता को लेकर भोपाल स्तर से आपत्ति ली गई। सैंपल जांच रिपोर्ट श्हाई टर्बिडिटीश् (अत्यधिक गंदलापन-मटमैला) पाई गई। 18 मई को संभागायुक्त ने नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब मांगा।

रंगशाही ने जवाब देने के लिए मांगे दस्तावेज

मामले में रंगशाही ने अब तक जवाब नहीं दिया। उन्होंने मामले से जुड़े डॉक्यूमेंट मांगे थे, जो लेट मिले हैं। अब वे नोटिस का जवाब देंगे। रंगशाही ने बताया कि उन्हें दस्तावेज प्राप्त हो गए हैं। अब वह जवाब देंगे। उल्लेखनीय है कि रंगशाही पर सितंबर-अक्टूबर 2025 में सीएम दौरे के दौरान हेलीकॉप्टर में फूड बास्केट नहीं रखने और ड्यूटी में चूक के आरोप लगे थे। तब भी उन्हें नोटिस दिया गया था।

रंगशाही ने मामले को साजिश बताया

नोटिस के बाद जिला आबकारी अधिकारी विनय रंगशाही ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अपने विरुद्ध एक सोची-समझी साजिश बताते हुए कहा है कि उनके विभाग को दूसरे विभाग के उत्तरदायित्व क्यों सौंपे जा रहे हैं? जब उन्होंने इस वीआईपी पेयजल व्यवस्था के उत्तरदायित्व को संबंधित विभाग (पीएचई/सत्कार) को सौंपने की बात कही, तो तत्कालीन कलेक्टर द्वारा उन पर व्यक्तिगत रूप से यह कार्य करने के लिए भारी दबाव बनाया गया था।

कलेक्टर और रंगशाही में चल रही खींचतान

शाजापुर कलेक्टर ऋजु बाफना और जिला आबकारी अधिकारी रंगशाही का विवाद पहले से चला आ रहा है। बाफना ने रंगशाही के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव उज्जैन संभाग आयुक्त आशीष सिंह को भेजा था, जिसके बाद 16 फरवरी को उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि, इससे पहले ही 20 जनवरी को रंगशाही से प्रभार छीनकर उनके अधीनस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी निमिषा परमार को सौंप दिया गया था।

गौरतलब है कि इस एकतरफा कार्रवाई के खिलाफ विनय रंगशाही ने हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने रंगशाही के निलंबन आदेश पर श्स्टेश् (रोक) लगा दिया। हाईकोर्ट ने मामले की कड़ियों को जोड़ते हुए पाया कि कलेक्टर ने संभाग आयुक्त को रंगशाही को सस्पेंड करने की अनुशंसा बाद में भेजी, लेकिन अपने स्तर पर अधीनस्थ अधिकारी परमार को जिला आबकारी अधिकारी का प्रभार पहले ही दे दिया था। अदालत ने माना कि ऐसी जल्दबाजी से कलेक्टर की मंशा पर गंभीर सवाल उठता है।

मोहर्रम में नौ दिन बंद रहेगी दुकानें व कारोबार

माही की गूंज, आम्बुआ

इस्लामिक कैलेंडर का नया वर्ष 15 जून सोमवार से शुरू हो रहा है। इस वर्ष शिया दाउदी बोहरा समाज के 53 वें धर्मगुरु अली कदर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब लंदन में मोहर्रम पर्व मनाकर पूरे विश्व में गम-ए-हुसैन का पैगाम देंगे। इस वर्ष सैयदना साहब ने मोहर्रम पर्व के दौरान समाजजन से अपना व्यापार-कारोबार पूर्ण रूप से बंद रखने का फरमान दिया है। इसी तारतम्य में मोहर्रम शुरू होने से पूर्व सभी कार्यालय और विद्यालयों में अवकाश के साथ व्यापारी, इंटरनेट मीडिया, व्हाटसएप, मेल, स्टेट्स, बैनर आदि माध्यमों से व्यापारिक कारोबार में किसी को परेशानी न हो, इस बारे में अवगत करवाया जा रहा है।

देश-विदेश से हजारों की तादाद में अनुयायी सैयदना साहब के साथ मोहर्रम पर्व में शामिल होने के लिए लंदन पहुंच रहे हैं। मोहर्रम के दौरान सैयदना साहब के कुछ प्रवचन की वीडियो रिकार्डिंग का लाभ भी हर शहर में मिलेगा। मोहर्रम का त्योहार 1400 वर्ष पूर्व पैगंबर साहब के नवासे इमाम हुसैन की शहादत की याद के रूप में मनाया जाता है।

शांति समिति की बैठक संपन्न

माही की गूंज, आम्बुआ।

इस्लामिक कैलेंडर का नया वर्ष 15 जून से दिन सोमवार से शुरू हो रहा है, लगभग 1400 वर्ष पूर्व पैगंबर साहब के नवासे इमाम हुसैन की शहादत हुई थी जिसकी याद में मोहर्रम मनाया जाता है। क्षेत्र में अमन-चौन और शांति पूर्वक आयोजन संपन्न हो इस हेतु आम्बुआ थाना प्रांगण में थाना प्रभारी मोहन सिंह डावर की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें सदस्यों से विभिन्न सुझाव मांगे गए तथा शासन प्रशासन के निर्देशानुसार कार्य क्रम संपन्न कराने पर विचार किया गया, बैठक में हिंदू, मुस्लिम तथा बोहरा समाज के लोगों ने भाग लिया।

गैस के दाम पुन: बढ़ाए जाने से ग्रहणियों में भारी आक्रोश

माही की गूंज, आम्बुआ।

विगत महिनों से चली आ रही गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच एक बार पुनः सिलेंडर की कीमत बढ़ा दिए जाने से क्षेत्र की ग्रहणियों में नाराजगी देखी जा रही है। विगत महिनों से युद्ध के हालातों के बीच कच्चे तेल के साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के कारण इनके भावों में बढ़ोतरी होती आ रही है कुछ दिनों पूर्व व्यावसायिक सिलेंडरों के साथ ही घरेलू सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी मगर अब पुनः 29 रू की बढ़ौतरी ने परेशानी में डाल दिया है मध्यवर्गीय परिवारों तथा गरीब परिवारों की कमर तोड दी। घरों का बजट बिगड़ता जा रहा है इस मंहगाई के दौर में अतिआवश्यक वस्तु की श्रेणी में आने वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी महिला वर्ग को परेशान कर रही है, जिसका सभी ओर विरोध किया जा रहा है।

क्या कहती है ग्रहणियां

1. इस मंहगाई के बीच बार बार गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से रसोईघर का बजट बिगड़ता जा रहा है।

2. रसोईघर में काम आने वाली लगभग सभी सामग्रियां महंगी होती जा रही है और उसी में गैस सिलेंडर महंगा हो गया है घर कैसे चलेगा? - श्रीमती तारामणि वर्मा ग्रहणी

3.दिनों दिन बढ़ती मंहगाई के बीच गैस सिलेंडर के भाव नहीं बढ़ना चाहिए थे भाव कम करना चाहिए। - श्रीमती संगीता चौहान ग्रहणी

26 विद्यार्थियों का भारतीय सेना में चयन

माही की गूंज, शुजालपुर।

नगर की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था आनंदम सुपर 50 एकेडमी के 26 विद्यार्थियों के भारतीय सेना में चयन होने पर भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में चयनित विद्यार्थियों का सम्मान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।

कार्यक्रम की अध्यक्षता देवेंद्र तिवारी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश मंत्री क्षितिज भट्ट उपस्थित रहे। विशेष अतिथि के रूप में लीलाधर शर्मा, भगवान सिंह यादव, राहुल सोलंकी, हेमंत पुष्पद, अभिनंदन जैन, निर्मल राठौर एवं आदर्श कुशवाह सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

समारोह में अतिथियों एवं चयनित विद्यार्थियों का भारत माता का चित्र, श्रीफल एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान किया गया। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय सेना में चयनित होना गौरव की बात है। उन्होंने युवाओं को राष्ट्रसेवा, अनुशासन और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान युवा संवाद का भी आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए और अतिथियों से मार्गदर्शन प्राप्त किया।

इस अवसर पर संस्था संचालक आनंद परमार, दिलीप यादव, केदार राजपूत, खान सर, दीपक सर, हेमंत सर एवं विनोद सर सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी, अभिभावक एवं नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन पूर्व पार्षद एवं सामाजिक कार्यकर्ता पं. प्रवीण जोशी ने किया तथा आभार प्रदर्शन केदार राजपूत ने व्यक्त किया।

डंफर की टक्कर से तीन भैंसों की मौत, एक गंभीर घायल

माही की गूंज, आम्बुआ।

थाना क्षेत्र के ग्राम पनवानी के कृषक की भैंसें जोकि रात्रि में घर जा रही थी को सड़क पार करने के दौरान एक डंफर ने जोर दार टक्कर मारी जिससे तीन की मौत होने तथा एक गंभीर रूप से घायल होने के समाचार है,वाहन चालक की तलाश जारी है, थाना आम्बुआ में प्रक्रण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

गूंज संवाददाता को मिली जानकारी अनुसार ग्राम पनवानी थाना क्षेत्र आम्बुआ निवासी नरसिंह पिता जोहरिया भूरिया ने बताया कि उसकी चार भैंसें रात को घर आ रही थी सभी एक झुंड में चलती हुई सड़क पार कर रही थी तभी एक डंफर वहां से गुजरा जिसके चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन तेज गति से दौड़ाया तथा भैंसों को टक्कर मारी जिससे तीन भैंसों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई तथा एक गंभीर रूप से घायल हुई है घटना इतनी ह्रदय विदारक रही कि एक भैंस डंफर में फंस जाने से उसकी गर्दन बहुत दूर जा कर गिरी जबकि धड़ घटना स्थल पर पड़ा हुआ था।

फरियादी नरसिंह भूरिया की सुचना पर थाना आम्बुआ में अ क्र 176/2026 धारा 281,324 बी एस एस के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया गया है।

लंबे समय से फरार स्थायी वारंटी गिरफ्तार

माही की गूंज, शाजापुर। शाजापुर पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार स्थाई वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक शाजापुर यशपाल सिंह राजपूत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवीय तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) शाजापुर अजय कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक अरविन्द सिंह तोमर द्वारा स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु एक विशेष टीम गठित की गई थी। गठित टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए थाना मोहन बड़ोदिया का लंबे समय से फरार स्थायी वारंटी सलीम खां पिता सत्तार खां, निवासी अलीसरखेड़ा, थाना सलसलाई को बस स्टैंड सारंगपुर, जिला राजगढ़ से गिरफ्तार किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के पश्चात उसे नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। उक्त कार्रवाई में उपनिरीक्षक अरविन्द सिंह तोमर थाना प्रभारी, प्रधान आरक्षक हेमेन्द्र सिंह जादौन, आदि की भूमिका रही।

गायत्री मंदिर के पुनर्निर्माण का भूमिपूजन सम्पन्न

माही की गूंज, शुजालपुर।

फ्रीगंज स्थित गायत्री मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य का भूमिपूजन समारोह श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने सहभागिता कर मंदिर पुनर्निर्माण कार्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार एवं धार्मिक अनुष्ठानों के बीच भूमिपूजन किया गया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने वेदमाता गायत्री के जयकारों के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र समाज को संस्कार, अध्यात्म और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। गायत्री मंदिर का पुनर्निर्माण क्षेत्र के श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

उन्होंने कहा कि वेदमाता गायत्री एवं परम पूज्य आचार्य भगवान की कृपा से मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है, जो समाज में आध्यात्मिक चेतना के प्रसार का माध्यम बनेगा। कार्यक्रम में गायत्री परिवार के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

भूमिपूजन के साथ ही मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया। श्रद्धालुओं ने मंदिर के भव्य स्वरूप में पुनर्निर्माण की कामना करते हुए क्षेत्र में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की।

जैविक खाद से पैदा हो रही आम की फसल का जिलाधीश ने किया अवलोकन

माही की गूंज, आम्बुआ।

समीप ग्राम बोरझाड में स्थित ठाकुर परिवार के आम बगीचे का अवलोकन आलीराजपुर जिला कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर द्वारा किया गया। यहां पर अनाज से लेकर फल आदि का उत्पादन जैविक पद्धति से किया जाता है, उन्होंने जैविक खाद एवं कीटनाशक दवा आदि के विषय में संपूर्ण जानकारी कृषक ठाकुर लोकेंद्र सिंह राठौर से ली।

जिलाधीश श्रीमती मीनू माथुर जिला मुख्यालय से जोबट प्रवास के दौरान कुछ समय के लिए बोरझाड स्थिति ठाकुर कृषि फार्म पहुंची जहां पर उन्नत कृषक ठाकुर लोकेंद्र सिंह राठौर ने स्वागत किया तथा आम बगीचे का अवलोकन कराया। यहां पर जिलाधीश श्रीमती मीनू माथुर ने जैविक खाद एवं कीटनाशक दवा बनाने की विधि की जानकारी प्राप्त की तथा जैविक खेती से संबंधित अनेक जानकारियां ऋषक ठाकुर लोकेंद्र सिंह राठौर द्वारा प्रदान की गई। आम की विभिन्न किस्मों के विषय में तथा उत्पादन एवं बाजार में बिक्री मार्केटिंग की जानकारी के बाद कृषक ठाकुर लोकेंद्र सिंह राठौर द्वारा मधुमक्खी पालन हेतु शासकीय योजनाओं के तहत मांग रखी। जिस पर कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर विचार करने का आश्वासन दिया गया है। स्मरण रहे कि यहां जैविक खाद से फलों के साथ ही खाद्यान्न जैसे गेंहू चना तथा सब्जियां भी जैविक पद्धति से पैदा की जाती है, क्षेत्र में अभी एक मात्र कृषक ठाकुर लोकेंद्र सिंह राठौर परिवार है जो जैविक खाद एवं कीटनाशक दवा का उपयोग कर रहे हैं तथा उर्वरक एवं कीटनाशक दवा स्वयं तैयार कर रहे हैं, जिलाधीश द्वारा प्रशंसा भी की गई। स्मरण रहे कि ठाकुर लोकेंद्र सिंह राठौर ने वर्ष 2017 में जैविक खेती का प्रशिक्षण लिया था तथा तभी से यह कार्य करते आ रहे हैं।

खाद्य सुरक्षा विषय पर जिला स्तरीय सलाहकार समिति की समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन

माही की गूंज, आलीराजपुर।

कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में खाद्य सुरक्षा विषय पर जिला स्तरीय सलाहकार समिति समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने और लंबित गंभीर मामलों के त्वरित निराकरण को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जानकारी दी कि जिले में निरंतर निरीक्षण और भ्रमण के माध्यम से मिलावटी खाद्य सामग्री पर नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्रित किए गए हैं। गत वर्ष लिए गए नमूनों में 3 इकाइयों की खाद्य सामग्री और 2 स्थानों से लिए गए कोल्ड ड्रिंक के सैंपल प्रयोगशाला परीक्षण में फेल पाए गए हैं। संबंधित इकाइयों के विरुद्ध प्रकरण तैयार कर अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं, जहां वे विचाराधीन हैं।

कलेक्टर श्रीमती माथुर ने निर्देश दिए कि वर्षा ऋतु से पूर्व राजस्व अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले में किसी भी स्थिति में दूषित एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों के विक्रय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही आमजन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के महत्व को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया, अपर कलेक्टर सोहन कनाश, संयुक्त कलेक्टर विरेन्द्र सिंह बघेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती ज्योति अमठ बघेल, अनुविभागीय अधिकारी सुश्री निधी मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

माही की गूंज की खबर पर लगी मुहर, एक साल पहले फर्जी पट्टों के खेल को किया था उजागर

जब-जब मामला उठा, जिम्मेदारों ने कार्रवाई की बजाय कर वा दिया समझौता, सामुहिक शिकायत के बाद एक बार फिर मामला चर्चा में

मामला : पट्टो के नाम पर सरकारी भूमि बेचने की बंदरबांट का, सरपंच-सचिव सहित जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई या होगा एक और बड़ा भ्रष्टाचार उजागर

माही की गूंज | अंचल की हलचल

जमीन पट्टे के नाम हुई धोखाधड़ी का मामला कलेक्टर के पास पहुंचा

जनसुनवाई में लगाई कलेक्टर से कार्रवाई की गुहार, एसडीएम के निर्देश के बाद नहीं हुई कोई जांच

ईमानदार आईएएस एसडीएम तनुश्री मीणा के सामने धोखेबाज ग्राम पंचायत की जांच की कड़ी चुनौती

सरकारी भूमि पर अवैध पट्टे के नाम पर वसूली की शिकायत लेकर महिला पहुँची जनसुनवाई में, थाने पहुँचा मामला

करोड़ो का झोल आ सकता है सामने, शिकायतकर्ता पर लेन-देन कर मामला निपटाने का दबाव

माही की गूंज | झाबुआ | 15 मई 2025 | 8

लेन-देन कर कागज पर जारी कर दिए पट्टे, मौके पर जमीन के अते-पते नहीं

वाह सारंगी वाह: भूमि पर पट्टे देने का अजीब ही रचा इतिहास

तीन साल से झूला रही पंचायत के खिलाफ जन सुनवाई में धोखाधड़ी की शिकायत

एक वर्ष पूर्व माही की गूंज में फर्जी पट्टे देने के मामले को लगातार खबरों के माध्यम से किया था उजागर।

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

लगभग एक साल पहले पेटलावद की सबसे ज्यादा राजस्व आय करने वाली पंचायत सारंगी में अवैध पट्टों के नाम पर शासकीय भूमि बेचने का बड़ा मामला माही की गूंज ने मय दस्तावेज उजागर किया था। खबर सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक हड़कंप मच गया और जिम्मेदार ग्राम पंचायत सारंगी पर कार्रवाई के दावे करने लगे। इस बीच ग्राम पंचायत सारंगी की सरपंच फून्दीबाई पर शिकायतकर्ताओं को डराने-धमकाने के गंभीर आरोप लगे और शिकायतकर्ताओं को पुलिस की शरण लेनी पड़ी। इतना ही नहीं, मामले में जांच अधिकारी तक ने शिकायतकर्ताओं को बयान के लिए रविवार को जनपद पंचायत कार्यालय में बुलाया और नहीं आने पर शिकायत फर्जी होने और उल्टी कार्रवाई करने तक की अप्रत्यक्ष धमकी दी। हर तरह से शिकायतकर्ताओं पर दबाव बनाकर आखिर शिकायत का निराकरण आपसी समझौते से करवाया गया। सरपंच ने दोनों शिकायतकर्ताओं को पट्टों के नाम पर ली गई राशि लौटाने की बात कही, जिसमें ग्राम के कुछ वरिष्ठ लोगों ने इसकी जवाबदारी ली और शिकायतकर्ताओं को नियत समय पर राशि लौटाकर मामले को खत्म किया गया। लेकिन ग्राम पंचायत सारंगी और जनपद के अधिकारी यह भूल गए कि, यह सिर्फ उस बहुत बड़े भ्रष्टाचार और सरकारी जमीन बेचने के मामले के उजागर होने की शुरुआत भर है। एक बार फिर एक साल बाद सारंगी पंचायत का भ्रष्टाचार का जिन्न, चिराग से बाहर आया।

सोमवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद सामने आया मामला

ग्राम सारंगी में थांदला-बदनावर मार्ग से लगी राजस्व की बेशकीमती शासकीय भूमि पर गांव के ही कुछ लोगों ने रातों-रात निर्माण शुरू कर दिया और देखते ही देखते लोहे के एंगल और चद्दर शेड तैयार हो गए। बताया जा रहा है कि, यहां ग्राम पंचायत सारंगी की सरपंच ने बकायदा चूने की लाइनिंग कर लोगों को प्लॉट दिए, जिनको पूर्व में नियम विरुद्ध पट्टे भी दिए गए थे। मामला राजस्व विभाग के पास पहुंचा, लेकिन अतिक्रमणकर्ता पट्टे होने के नाम पर निर्माण कार्य रोकने को तैयार नहीं हुए और गत मंगलवार को मेघनगर में आयोजित विशेष जनसुनवाई में भी इसकी शिकायत हुई। कलेक्टर के संज्ञान में मामला आने के बाद सोमवार को पेटलावद और सारंगी के अमले ने मौके पर पहुंचकर बैंकहो लोडर मशीन (जेसीबी) के माध्यम से शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया। जिन लोगों ने निर्माण किया था, उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को पट्टे होने का हवाला दिया, लेकिन ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने का प्रावधान नहीं होने का हवाला देकर अतिक्रमण हटा दिया गया। पट्टों के आधार पर जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया था, वे वैध नहीं हैं।

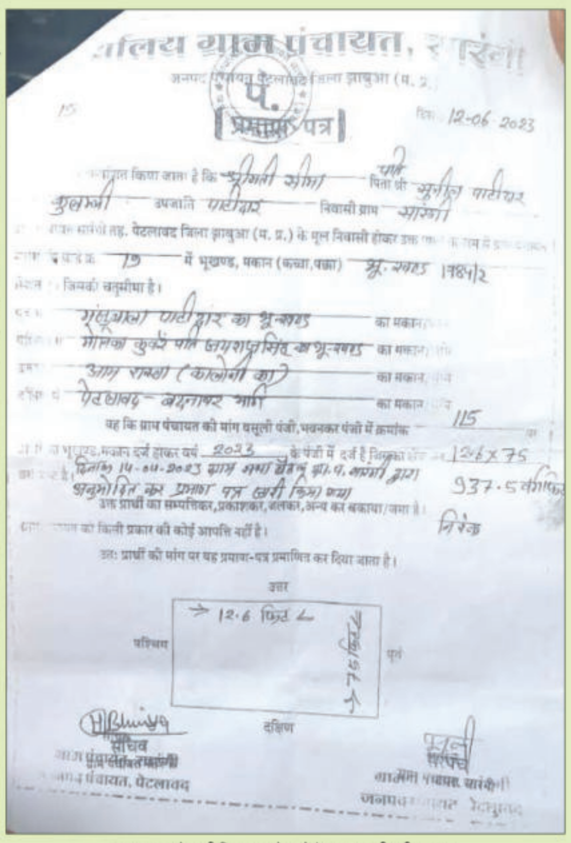

इस प्रकार से जारी किए गए पट्टे, पट्टे के नाम पर ली बड़ी रकम।

महिला और बेटियां सामूहिक रूप से पहुंचीं जनसुनवाई में, लगाया पट्टों के नाम पर वसूली का आरोप

ग्राम पंचायत सारंगी में शासकीय भूमि के नाम पर लोगों से लाखों रुपए लेकर कथित रूप से फर्जी पट्टे जारी करने का मामला एक बार फिर उजागर हुआ। मंगलवार को पेटलावद जनसुनवाई में बड़ी संख्या में पीड़ितों ने आवेदन सौंपकर सरपंच-सचिव के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा जमा कराई गई राशि वापस दिलाने की मांग की। पीड़ितों का आरोप है कि, ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों ने शासकीय भूमि का पट्टा देने के नाम पर लोगों से पांच लाख से लेकर आठ लाख रुपए तक वसूले। बदले में उन्हें पट्टे और रसीदें दी गईं तथा भरोसा दिलाया गया कि, जमीन पूरी तरह वैध है। लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई के बाद उन्हें जानकारी मिली कि, उनके पट्टे फर्जी हैं और उनके साथ धोखाधड़ी हुई है।

वसुला का आकड़ा एक करोड़ के पार, लगे गंभीर आरोप

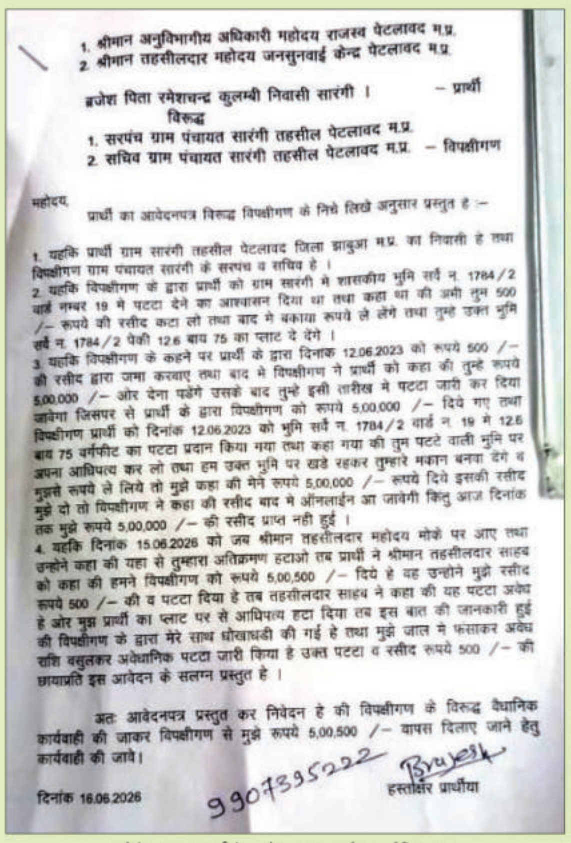
1. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व पेटलावद म.प्र.
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय जनसुनवाई केन्द्र पेटलावद म.प्र.

ब्रजेश पिता रमेशचन्द्र कुलम्बी निवासी सारंगी । — प्रार्थी

विरूद्ध

1. सरपंच ग्राम पंचायत सारंगी तहसील पेटलावद म.प्र.
2. सचिव ग्राम पंचायत सारंगी तहसील पेटलावद म.प्र. — विपक्षीगण

महोदय,

प्रार्थी का आवेदनपत्र विरूद्ध विपक्षीगण के निचे लिखे अनुसार प्रस्तुत है :—

1. यहकि प्रार्थी ग्राम सारंगी तहसील पेटलावद जिला झाबुआ म.प्र. का निवासी है तथा विपक्षीगण ग्राम पंचायत सारंगी के सरपंच व सचिव है ।
2. यहकि विपक्षीगण के द्वारा प्रार्थी को ग्राम सारंगी मे शासकीय भुमि सर्वे न. 1784/2 वार्ड नम्बर 19 मे पटटा देने का आश्वासन दिया था तथा कहा था की अभी तुम 500 /— रूपये की रसीद कटा लो तथा बाद मे बकाया रूपये ले लेंगे तथा तुम्हे उक्त भुमि सर्वे न. 1784/2 पैकी 12.6 बाय 75 का प्लाट दे देंगे ।
3. यहकि विपक्षीगण के कहने पर प्रार्थी के द्वारा दिनांक 12.06.2023 को रूपये 500 /— की रसीद द्वारा जमा करवाए तथा बाद मे विपक्षीगण ने प्रार्थी को कहा की तुम्हे रूपये 5,00,000 /— और देना पड़ेंगे उसके बाद तुम्हे इसी तारीख मे पटटा जारी कर दिया जावेगा जिसपर से प्रार्थी के द्वारा विपक्षीगण को रूपये 5,00,000 /— दिये गए तथा विपक्षीगण प्रार्थी को दिनांक 12.06.2023 को भुमि सर्वे न. 1784/2 वार्ड न. 19 मे 12.6 बाय 75 वर्गफीट का पटटा प्रदान किया गया तथा कहा गया की तुम पटटे वाली भुमि पर अपना आधिपत्य कर लो तथा हम उक्त भुमि पर खडे रहकर तुम्हारे मकान बनवा देंगे व मुझसे रूपये ले लिये तो मुझे कहा की मेने रूपये 5,00,000 /— रूपये दिये इसकी रसीद मुझे दो तो विपक्षीगण ने कहा की रसीद बाद मे ऑनलाईन आ जावेगी किंतु आज दिनांक तक मुझे रूपये 5,00,000 /— की रसीद प्राप्त नही हुई ।
4. यहकि दिनांक 15.06.2026 को जब श्रीमान तहसीलदार महोदय मोके पर आए तथा उन्होने कहा की यहा से तुम्हारा अतिक्रमण हटाओ तब प्रार्थी ने श्रीमान तहसीलदार साहब को कहा की हमने विपक्षीगण को रूपये 5,00,500 /— दिये है वह उन्होने मुझे रसीद रूपये 500 /— की व पटटा दिया है तब तहसीलदार साहब ने कहा की यह पटटा अवेध हे ओर मुझ प्रार्थी का प्लाट पर से आधिपत्य हटा दिया तब इस बात की जानकारी हुई की विपक्षीगण के द्वारा मेरे साथ धोखाधडी की गई हे तथा मुझे जाल मे फंसाकर अवेध राशि वसुलकर अवेधानिक पटटा जारी किया है उक्त पटटा व रसीद रूपये 500 /— की छायाप्रति इस आवेदन के सलग्न प्रस्तुत है ।

अतः आवेदनपत्र प्रस्तुत कर निवेदन हे की विपक्षीगण के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाकर विपक्षीगण से मुझे रूपये 5,00,500 /— वापस दिलाए जाने हेतु कार्यवाही की जावे।

दिनांक 16.06.2026 9907395222 Brujesh
हस्ताक्षर प्रार्थीया

पट्टों के नाम पर वसूली के आरोप लगाकर दर्ज करवाई शिकायत।

जनसुनवाई में दिए गए एक आवेदन में आवेदक बृजेश कुलम्बी ने आरोप लगाया है कि, ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव ने शासकीय भूमि पर कब्जा दिलाने के नाम पर पहले अग्रिम राशि ली और बाद में कुल पांच लाख रुपए से अधिक की रकम लेकर पट्टा जारी कर दिया। आवेदक का कहना है कि, जब तहसीलदार की कार्रवाई में उसे जमीन से हटाया गया, तब उसे पता चला कि पूरा पट्टा अवैध है। आवेदन में संबंधित राशि वापस दिलाने और दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की गई है।

जनसुनवाई में पहुंचे कई लोगों ने दावा किया कि, उन्होंने अपनी जीवनभर की जमा-पूंजी, जमीन के लिए पंचायत को दी थी। अब अतिक्रमण हटाने के बाद न जमीन बची और न ही पैसा, जिससे वे आर्थिक संकट में आ गए हैं। पीड़ितों ने प्रशासन से मांग की है कि, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, कथित रूप से जारी किए गए सभी फर्जी पट्टों की जांच हो, दोषी पाए जाने वाले सरपंच एवं सचिव पर कानूनी कार्रवाई की जाए तथा न्याय के साथ पीड़ितों को उनकी जमा राशि वापस दिलाई जाए।

सामूहिक शिकायत लेकर जनसुनवाई पहुंचे सारंगी के ग्रामीणजन।

पट्टे जारी करने का ही नहीं शासकीय भूमि बेचने का भी मामला, कई और भी भूमियां बेची गईं

वैसे तो इस मामले को पट्टों से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन पट्टे प्राप्त करने का अधिकार केवल भूमिहीन को है। वह भी सीधे ग्राम पंचायत के पास पट्टे जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। असल में पूरा मामला शासकीय भूमि बेचने का है, जिसके लिए लोगों से पट्टों के नाम पर मोटी रकम वसूली गई। इस मामले में केवल सरपंच-सचिव ही नहीं, बल्कि और भी बड़े लोग शामिल हैं, जिन्होंने अलग-अलग लोगों को पट्टे दिलाने के नाम पर दलाली की और मोटी रकम लेकर ऐसे लोगों को पट्टे जारी करवाए, जिनको पट्टे की पात्रता तक नहीं आती। सारंगी ग्राम पंचायत में ग्राम सहित सारंगी-पेटलावद मुख्य मार्ग पर लगी शासकीय भूमि पर जारी निर्माण और कब्जों की जांच की जाए, तो सारा मामला दूध की तरह साफ हो जाएगा।

सामान्य और ओबीसी को पट्टे, आदिवासी को नहीं

पंचायत अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत को पट्टे देने का अधिकार नहीं है। पट्टे जारी करने का कार्य अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास है, जो ग्राम पंचायत और तहसील की अनुशंसा पर पात्र व्यक्ति के लिए पट्टा जारी कर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र होने से सामान्य और पिछड़ा वर्ग को ग्राम पंचायत किसी भी स्थिति में पट्टे जारी नहीं कर सकती। इसके बावजूद सारंगी ग्राम पंचायत में सामान्य, पिछड़ा वर्ग और रसूखदारों को पट्टे जारी किए गए, जिसमें कई धनाढ्य और जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं।

एसडीएम तनुश्री मीणा के पाले में गेंद, क्या होगा दर्ज मामला

पिछले दो साल से खुद को पाक-साफ छवि में बनाए रखने वाली आईएएस एसडीएम राजस्व तनुश्री मीणा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्यों जनसुनवाई में एक वर्ष पूर्व हुई शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई...? अलग-अलग मामलों में एसडीएम के पास शिकायत पहुंचती रही और मैडम के अधीनस्थ अधिकारी जांच के नाम पर मामलों को लटकाते रहे। उधर सारंगी टप्पे की नायब तहसीलदार अंकिता भिड़े के संज्ञान में सब कुछ होने के बाद भी सारंगी सरपंच-सचिव सहित जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं की गई।

जीरो भ्रष्टाचार वाली पार्टी के सामने भी चुनौती, ईओडब्ल्यू के पास जाए मामला

इतने बड़े स्तर पर हुई हेरा-फेरी बिना सत्ताधारी नेताओं के शामिल हुए संभव नहीं। जीरो भ्रष्टाचार की मोदी जी की नीति पर यह मामला पानी फेरता नजर आ रहा है, क्योंकि हर बार शिकायत को सत्ता के नुमाइंदों के इशारे पर ही दबाया गया। चूंकि मामला अब एक-दो पट्टों तक सीमित नहीं है, सूत्रों की मानें तो सौ से ज्यादा पट्टे अवैध रूप से अपात्रों को जारी किए गए हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422